THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): For Zero Hour submissions, I have Mr. Kanaksinh Mohansinh Mangrola.

SHRI H. HANUMANTHAPPA (Karnataka): Mr. Vice-Chairman, Sir, when we asked the Chairman for suspension of the Question Hour to discuss this subject, he has ruled that after the Question Hour, this will be the first subject to be taken up. ..(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): You will be allowed to speak. Please sit down. Mr. Mangrola wants to raise a privilege matter.

—

QUESTIONS OF PRIVILEGE

श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला (गुजरात) माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, 23 मई को मेरा एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह था कि सारे देश में जो सीरियल चल रहे हैं इनमें कौन से सीरियल पापुलर हैं । माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि इम्तिहान, श्रीकृष्णा और जुनून है । मेरा बहुत महत्व का प्रश्न यह था कि इन तीनों सीरियल्ज से सरकार कितनी इनकम है । माननीय मंत्री जी 12 करोड़ रुपये इनकम बताई । सेकेंड मई को श्री शारदा महन्ती जी के प्रश्न में इसी हाऊस में उन्होंने यह इनकम इन सीरियल्ज से 28 करोड़ रुपये बताई । उपसभाध्यक्ष महोदय, पूरे सदन को उन्होंने गुमराह करने की कोशिश की है । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हू कि इसके बारे में पूरी जांच कारवाई जाए क्योंकि उन्होंने गुमराह करने की कोशिश की है। मेरी मांग यह है कि प्रिविलेज मोशन मूव किया जाए । (**व्यवधान**)

श्रीमती सुषमा स्वराज (हरियाणा) : बहुत गम्भीर प्रश्न है । एक ही मंत्री जवाब दे रहे हैं (**व्यवधान**)

श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला : मेरा महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि दोनों जवाबों में फर्क क्यों आता है ! (**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष (**श्री मोहम्मद सलीम**) : आपने प्रिविलेज मोशन दिया हैं । ?

श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला : जी हां, दिया है। । मेरी मांग है इस पूर मामले की जांच की जाए ।

उपसभाध्यक्ष (**श्री मोहम्मद सलीम**) चयरमैन साहब कैसीडर करेंगे ।

—

RE. NEED FOR REHABILITATION OF DALIT FAMILIES IN KADI TOWN OF GUJARAT

श्री अजीत जोगी (मध्य प्रदेश) : उप सभाध्यक्ष महोदय, म आपके माध्यम से एक अत्यन्त ही गम्भीर, दर्दनाक, रोंगटे खड़े करने वाले और दिल दहला देने वाले एक ऐसे हादसे के विषय में जो दलितों से संबंधित है ..(**व्यवधान**) पहले सुन लीजिए ....

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे (गुजरात) : थोड़ी सी परमिशन मुझे भी दीजिए । ये कह लें फिर मुझे एक मिनट दीजिए... (**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष (**श्री मोहम्मद सलीम**) : ठीक है । आपको भी मौका मिलेगा । जिनके नाम है लिस्ट के अनुसार हम उनको बुलाएंगे ।

श्री अजीत जोगी : आप भी अपनी बात कहिएगा ।

उसके विषय में आपके माध्यम से सदन का और राष्ट्र का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । गुजरात के मेहसाना जिले में कड़ी नाम का एक नगर है । वहां 12 मई को तुलसी नाम का एक दलित अपनी भतीजी के साथ एक दुकान में कुछ खरीदने गया । केवल 50 पैसे को लेकर दुकानदार से उसकी बातचीत हुई । दुकानदार और उसके सेल्समैन ने

मिलकर उसकी पिटाई चालू कर दी यह कहकर कि तुम दलित होकर हमसे यह सवाल करते हो कि हम तुमसे 50 पैसे ज्यादा ले रहे है । उसकी इतनी पिटाई की कि उसकी नाक से खून निकलने लगा । उसकी छोटी भतीजी से देखा नहीं गया । वह अपने मुहल्ले में अपने घर गयी अपने रिश्तेदारो को बताने कि उसके चाचा की इस तरह से वहां पिटाई की जा रही है । जब उसके घर के रिश्तेदार उस दुकान में आ गए तो वहां वह दुकानदार और उसके आसपास के सभी दुकानदार इकटठे हो गए और सौभाग्य या दुर्भाग्य से इस घटना की सूचना वहां के स्वास्थ्य मंत्री श्री नितिन पटेल जी को दी गयी । वे भी घटना स्थल पर आए । उन्होंने घटना स्थल पर..

श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला (गुजरात) : महोदय... (**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) : मंगरोला जी आप बैठ जाइए । जोगी जी आप बोलिए ।

श्री अजीत जोगी : मैं कह लू फिर आप अपनी बात कहिएगा । मैं वहां होकर आया हूं । मने जो घटना की तहकीकात की है उसके अनुसार बता रहा हूं ।

वे वहां आ गए । उन्होंने पहले यह कहना चालू किया कि ये लोग इसी तरह का वर्ताव करते रहे हैं, इनको कुछ सबक सिखाना आवश्यक है । इसलिए सब लोग दुकानें बंद करें । सबने दुकानें बंद की । करीब 3–4 हजार लोग इकट्ठे हो गए । वह व्यक्ति तुलसी जो दलित है वह पुलिस थाने में गया । पुलिस थाने में चूंकि मिनिस्टर साहब का इंटरस्ट था इसलिए उसकी रिपोर्ट भी नहीं लिखी गयी उल्टे उसको ही थाने में बन्द कर दिया गया । यह जो माब था, करीब 4–5 हजार लोक इकट्ठे होकर फिर उस मुहल्ले में गए जहां वह दलित रहता था । महोदय, यह मुहल्ला जैसा अक्सर होता है कि दलितों का मुहल्ला शहर के बाहर होता है, सौभाग्य से या दुर्भाग्य से कड़ी गांव में उसका विकास इस तरह से हुआ है कि दलितों का यह जो स्थान है अब शहर के बिल्कुल मध्य में आ गया है, सबसे बहुमूल्य भूमि वहां पर है । वहां पर एक शापिंग सेंटर जैसा बनज गया हैंज जहां पर दलितों के मकान और दुकानें हैं । उस पर इनकी निगाहें बहुत दिनों से लगी हुई हैं कि किस तरह से दलित शहर के मध्य में रह रहे हैं, किस तरह से दलित अपने बिजिनेस अपने व्यापार अपने व्यवसाय में हमसे बराबरी कर रहे हैं । इसलिए जब यह तेल वहां पर पहुंचा जिसका नेतृत्व वहां के मंत्री श्री नितिन पटेल कर रहे तो उन्होंने आव न देखा ताव और रह जो दुकानें थीं जिनके तेारे ; उनको मालूम था कि यहां से दलित तभी हट सकते हैं, जब इनकी ये दुकानें बुरी तरह से जलाकर दूस्तानाबूद कर दी जाए तो उन्होंने उन दुकानों को, उन दलितों को मारना पीटना चालू किया, लाठियों से राडों से और घासलेट, मिटटी का तेल तथा पेट्रोल लगाकर उन दुकानों में आग लगा दी ।

हमने स्थल पर जाकर देखा है । मेरे साथी माननीय सदस्य श्री कल्याण जी वहां थे, मेरे साथी श्री राजू परमार वहां थे । हमने जाकर देखा । महोदय, दलितों की 40 दुकानें बिल्कुल जला दी गयीं, बिल्कुल राख हो गयी हैं । दलितों के दो सौ परिवार उस जगह से इतने भय-भीत हो गए कि वे 12 तारीख से उस शहर को छोड़कर चले गए है आज तक वापस नहीं आए हैं । हमने उनसे अनुनय विनय की कि चलिए हम आपको आपके शहर वापस ले जाएंगे । पर वे इतने डरे हुए हैं इतने भयभीत हैं इतनी बुरी तरह से पीटे गए हैं, उनके घर जला दिए गए हैं, उनकी दुकानें जला दी गयी हैं कि वे कड़ी गांव को छोड़कर गांधीनगर में बैठे हुए हैं । जहां हम उनसे मिलकर आए । महोदय, मेहसाना से निकलकर गांधीनगर जो गुजरात की राजधानी है वहां पर वे धरना दिए हुए हैं । मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह इस घटना में जो कार्यवाही हुई वह बिल्कुल एक

पक्षीय हुई है । हमला हुआ दलितों पर, मारे गए दलित, दुकानें जलीं दलितों की, घर जले दलितों के और पुलिस ने कार्यवाही किस पर की ? दलितों पर की । महोदय, दलितों की रिपोर्ट नहीं लिखी गयी । दलितों ने जो रिपोर्ट लिखवायी है, उसके अनुसार दूसरों पर कार्यवाही होनी थी । हम वहां के जिला कलक्टर से मिले, जिले के एम०पी० से मिले और उन के साथ मौके पर गए । हम ने गुजरात के मुख्य मंत्री जी से भी मिलने का अनुरोध किया, पर हम जानते हैं कि वह हम से मिल नहीं सकते थे, वह हम को फेस नहीं कर सकते थे क्योंकि वहां जो कार्यवाही हुई है, वह एक-पक्षीय और एकतरफा हुई है । दलितों की रिपोर्ट पर जो गिरफ्तारियां हुई हैं, वह नाम दिखाने के लिए हुई हैं । बड़ी गांव का कोई भी ऐसा सवर्ण नेता या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि उस घटना में था, गिरफ्तार नहीं किया गया है । महोदय, शादी की बारात में कुछ लोग आए थे । ऐसे लोग थे जोकि दूसरे गांव से आए थे और यह दिखाने के लिए कि हम दूसरे पक्षर पर कार्यवाही कर रहे हैं, बारात में उन लोगों की गिरफ्तारियां की गयी । महोदय, गुजरात सरकार के एक आदरणीय मंत्री महोदय में उनका नाम नहीं लेना चाहता, जो कि हमारे वर्ग के हैं, हमसे मिले और उन्होंने बताया कि मेरे गांव से बारात आई थी, उसमें से तीन आदमी उस तरफ से गिरफ्तार किए गए यह दिखाने के लिए कि हमने दूसरे पक्ष से भी गिरफ्तारियां की हैं । इस तरह से वहां पुलिस कार्यवाही और प्रशासन की कार्यवाही पूरी एकतरफा हुई है । उसके बाद जब हल्ला मचा, हमारी पार्टी के लोगों ने, दूसरी पार्टी के लोगों ने, महोदय मैं इसमें किसी पार्टी को बात नहीं करना चाहता, वहां हम इस घटना में जिन दलितों की दुकानें जली हैं, उनमें भारतीय जनता पार्टी के लोग भी थे । भारतीय जनता पार्टी के ब्लाक के उपाध्यक्ष महोदय उसमें थे । श्री दया भाई राठौर जोकि वहां के उपाध्यक्ष थे, कांतिलालाल सोलंकी जो कि इन्हीं नितिन भाई पटेल के चुनाव में उस मोहल्ले के एजेंट थे, ये भी वहां थे । इन लोगों की भी दुकानें जली हैं, इनका भी घर जला है । इन्होंने उनको रोकने की कोशिश की । इन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि हम तो आपके लोग हैं, आप क्यों हमारी दुकानें जला रहे हैं आप क्यों हमारे घर जला रहे हैं, आप क्यों हम पर लाठियां और लोहे की राड्स से प्रहार कर रहे हैं ? पर उनकी बात नहीं सुनी गयी और आज उसका नतीजा यह है कि ये लोग जो कि आप की पार्टी के इतने जिम्मेदार लोग थे, उन्होंने अपनी पार्टियां छोड़ दी हैं । महोदय, गांधीनगर में जो धरना दिया जा रहा है, वहां यह लोग भी बैठे हुए हैं । हम उनसे मिलकर आए हैं । इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह दल की बात नहीं है, यह पार्टी की बात नहीं है, इन लोगों पर सच में बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है महोदय, ये लोग इतने भयभीत हैं कि वहां वापिस नहीं जाना चाहते हैं और जो मुआवजा उन्हें दिया गया है, उसमें भी फेस की जा रही है । महोदय, हमने नुकसान का आकलन किया है जिसके अनुसार कम से कम करीब 40 लाख का उनका नुकसान हुआ है हमने कलेक्टर से पूछा कि आपने नुकसान का आकलन किया है ? कलेक्टर ने कहा कि करीब 14 लाख का नुकसान हुआ है । हमने पूछा कि आपने कितना मुआवजा दिया है ? उन्होंने हम को एक लिस्ट दी, उसके अनुसार 3 लाख 68 हजार रुपए 42 व्यक्तियों को दिए गए हैं । मैंने उस लिस्ट को एक-एक करके पढ़ा है, उसमें 42 के 42 नाम दलितों के हैं अर्थात् कलेक्टर की सूची के अनुसार जो नुकसान हुआ है, वह एकतरफा हुआ है । फिर हम अस्पताल गए, वहां रिकार्ड देखा कि कितने लोग वहां इलाज कराने, जांच कराने या एडमीशन लेने के लिए आए थे । हमने वह पूरी लिस्ट देखी । वह 30-32 लोगों की लिस्ट है जिसमें कि जो घायल वहां लाए गए थे, उनमें से कुछ लोगों को इलाज के बाद छोड़ दिया गया,

और कुछ लोगों को वहां एडमिट किया गया । महोदय, उनमें से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जाकि दलित न हो । यह भी सिद्ध करता है कि जो रिपोर्ट वह सारे-के सारे दलित थे, जिनका नुकसान हुआ वह क्योंकि स्वत: प्रशासन यह कहता है । महोदय, कलेक्टर से मेरी बात हुई और कलेक्टर ने स्वत: यह स्वीकार किया कि नितिन भाई पटेल ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) : आप संक्षप में बोलिए, इस विषय पर 16 लोग बोलने वाले हैं !

श्री अजीत जोगी : इसलिए मैं आपके माध्यम से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि यह बहुत ही गंभीर मसला है ।

श्री मोहिन्दर सिंह कल्याण (पंजाब) : उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिए तो आपको टाइम देना चाहिए । इन दलितों पर जुल्म और अत्याचार हुआ है और इस विषय से ज्यादा कीमती समय और क्या होगा ?

श्री अजीत जोगी : महोदय, इस घटना में दलितों पर बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है । वैसे तो दलितों पर अत्याचार होना गंभीर बात तो है ही, लेकिन यहां दलितों पर अत्याचार हुआ है एक बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति की परिस्थिति में, दलितों पर अत्याचार हुआ है एक ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में जिस पर कि संविधान ने, जिस पर कि कानून ने , जिस पर जनता ने, जिस पर प्रजातंत्र ने यह जवाबदेही दी है कि वह दलितों की रक्षा करे, लेकिन वह स्वत: वहां खड़े होकर दलितों को पिटाता रहे, दलितों को गालियां देता रहे, दलितों के मकानों को और दलितों की दुकानों को जलवाता रहे । एक ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में यह घटना घटी है, इसलिए यह अत्यन्त ही गंभीर मसला है।

महोदय, केन्द्र शासन की यह जवाबदेही है कि शड्यूल्ड कास्ट्स और शड्यूल्ड ट्राइब्स को सुरक्षा प्रदान करना, केन्द्र शासन की जवाबदेही है शड्यूल्ड कास्ट्स और शड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के लिए हर तरह की सहूलियतें प्रदान करना... इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, हमारे सदन के सम्मानीय नेता, गृह मंत्री जी यहां उपस्थित हैं, कि इस पर गुजरात सरकार से जानकारी लेकर सदन के सामने एक बयान दें, जिस पर हम लोग चर्चा कर सकें, जिस पर हम लोग बातचीत कर सकें । इस बीच में हाथ जोड़कर अपने भारतीय जनता पार्टी के साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि इसको आप दलीय रूप में कृपया मत लीजिए । वहां दलितों पर अत्याचार हुआ है, उनके साथ अन्याय हुआ है । ...(व्यवधान)...इसलिए एक ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा काम किया है, उसको किसी भी तरह से जस्टीफाई नहीं किया जा सकता, न्यायपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता । उनको आप अपने मंत्रिमंडल से निकालिए और दूध का दूध, पानी का पानी करने के लिए न्यायिक जांच कराइए । ..(व्यवधान)...अगर हम झूठ बोल रहे हैं, हम दो दिन जांच करके आए हैं, अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो आप इसकी एक न्यायिक जांच करवा लीजिए । इससे जो सही बात होगी, वह सामने आ जाएगी । ...(व्यवधान)मैं.. इसकी आप न्यायिक जांच करवा दीजिए। इस मंत्री को अपदस्थ करिए । हम चाहेंगे कि माननीय गृहमंत्री जी इस पर अपना बयान दें । यही मेरा अनुरोध है ।

SHRI H. HANUMANTHAPPA (Karnataka): Mr. Vice-Chairman, Sir, I do not want to go into the details of what Mr. Ajit Jogi has narrated. Sir, the moot question here is when the incident took place, the Minister of the Government was present. Why? What was his action? It is the moot question to be considered. And the crowd was armed with lathis, petrol, kerosene in his presence, Naturally the police had become one-sided. What was the ac-

tion of the police? Only the Harijan leaders were arrested, nobody else. If there was a quarrel between a shopkeeper and a Tulasi, and if the Tulasi was arrested, naturally the shopkeeper also should have been taken custody. Nobody had been arrested. This was the action of the police. This had happened with the influence of the Minister. The behaviour of the police shows that there was an instigation or an influence exerted by the Minister who was present on the spot. We had also gone to the hospital to see the Harijans. The hospital Superintendent had sent a message to the Police Station, "Please come and take their statements. The police had not gone to the hospital. The hospital authorities said—it was on record—that they had requested the police to come and take the statements of the victims but the police did not come. This was because of the influence of the Minister who was present there. Sir, 30 persons were injured, 67 families were affected and 200 families had migrated. Sir, you can imagine the magnitude of the incident. And nobody was booked from the other side! Whosoever were booked were all outsiders who had come for a marriage so that they could escape easily. Only for the name's sake some people were arrested. those who were not involved, those who were not even the residents of the village or the town. Those who had come for the marriage were arrested they were all outsiders. Sir, this shows the one-sided action of the police. This is what I am worried about the presence of the Minister and the action of the police, the omissions and commisions committed in their duties. Sir, without further arguing. I demand that at least the Minister who is responsible for the commission of these atrocities should be dismissed. Sir, a judicial inquiry be instituted and the investigation work be taken back from the local police because the Minister is involved. It should be handed over to CBI and the guilty should be booked under the Prevention of Atrocities Act and adequate compensation should be given. Sir, what is the compensation they have given? Houses were burnt, shops were destroyed. According to the Zila Collector's report, Rs. 8,750/- per family is being given to only 40 families. Sir, adequate compensation should be given. The Central Government cannot be a silent spectator of this incident because it is vested with the responsibility of protecting the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes against the atrocities. Sir, I request the hon. Home Minister to collect the information and come to the House so that we can have a discussion on this. Thank you.

श्री मोहिदर सिंह कल्याण : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं । आजाद हिन्दुस्तान का वह दतरीन दिन था 12 मई, 1995 का, जब कि एक सूबे के वजीर ने अपनी शियाया पर गुडों को लेकर हमला कर दिया । घंटों तक जुल्म का नंगा नाच होता रहा । गरीबों के मकान और दुकानें जलती रहीं, लोग दर्दनाक हद तक जख्मी हुए मगर उनकी मदद का कोई सहारा न हुआ । मेरा मतलब उस सियाह दिन से है जब भा0ज0पा0 हुकूमत के गुजरात सूबे के कादी कस्बे में नितिन पटेल नामी पटेल ने अपने गुंडों को साथ लेकर गरीब दलितों पर जनरल डायर की तरह जुल्म ढाए । जुल्म की इंतिहा तो देखिए कि ऐसी जलील हरकत करने वाले मुजरिमों के खिलाफ एक्शन लेने के बजाए मजलूम दलितों को जेल में बंद कर दिया । भा0ज0पा0

सरकार ने तो जर्मन के हिटलर की याद को ताजा कर दिया । यह नंगा फासिज्म है और भारत की जम्हूरियत के लिए इंतहाई खतरा है । सरकारी जुल्म की इस वारदात की बहुत गहराई से जांच करानी चाहिए । मैं तो यह कहूंगा कि इस जुल्म के बाद गुजरात मे भा0ज0पा0 सरकार ने हुकूमत करने का हक खो दिया है । कानून को फौरन हरकत मैं आना चाहिए ताकि डरे हुए, सहमे हुए महात्मा गांधी के लाडलों में ऐतमाद पैदा हो सके । गुजरात में तमाम दलित समाज का भा0ज0पा0 सरकार से विश्वास उठ चुका है । भारत सरकार को फौरन इस सम्बन्ध में सख्त कदम उठाने की बेहद जरुरत है।

मैं वहां 27–05–95 को गया था । सब प्रकार के लोगों से मिला—सरकारी और गैर सरकारी दोनों से । मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि कादी में इंडस्ट्री और दूसरे बिजनेस पर पटेलों की इजारा-दारी थी । भारत सरकार की दलितों को ऊपर उठाने की स्कीमों की वजह से वहां ये लोग भी बिजनेस में शरीक हो गए । बस यह बात नितिन पटेल और उसके साथियों को बर्दाश्त न हो सकी और वह दलितों से ईर्ष्या करने लगे और फिर यह हसद दुश्मनी में बदलता चला गया । ऐसा 1980–81 से होता चला आ रहा है । अब जब कि वे लोग हुकूमत में आ गए तो बदले और दुश्मनी की भावना और भड़क उठी । नतीजे के तौर पर दलितों के मकानों, दुकानों और सब तरह की जायदाद को लूट लिया, जला दिया, उनका बेरहमी से मारा-पीटा और गंभीर तौर पर जख्मी कर दिया । अगर यह कहा जाए कि दलित बस्ती को जलाकर राख कर दिया तो गलत नहीं होगा और यह सब जुल्म हुआ हुकूमत के वजीर नितन पटेल की सरपरस्ती और अगुवाई में, जो खुद मौके पर मौजूद रहकर अपन गुंडों को उकसा रहा था । 12 : 30 से लेकर 4 : 00 बजे शाम तक कादीं में जगल और शैतान का राज रहा । उसके बाद हुक्काम को जोग खुली और वह 4 : 00 बजे शाम वहां तशरीफ लाए । उस वक्त तक 39 दलित गंभीर तौर पर जख्मी हो चुके थे, उनकी दुकानों को लूटा जा चुका था या जलाया जा चुका था । वहां पर केरोसीन, लोहे की सलाखें और लकड़ी के बड़े-बड़े डंडे रखे हुए थे और वहां पर हमारे गरीब दलितों में से एक के यहां शादी हो रही थी, उसका जो पंडाल था, उसको भी जलाया गया और जंज में आए हुए जो कुछ लोग थे, उन लोगों को भी पकड़-पकड़ कर पुलिस थाने में बंद कर दिया गया । उपसभाध्यक्ष जी, . . . (**व्यवधान**) . . .

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) : कल्याण जी, आप जरा संक्षेप में बोलिए और भी बहुत लोग है, वे भी बोलना चाहते हैं बहुत गंभीर सवाल है । जरा जल्दी समाप्त कीजिए ।

श्री मोहिन्दर सिंह कल्याण : जो अखबारों में निकला है जिन लोगों के पांव तोड़े गए, टांगें तोड़ी गई और सिर फोड़े गए थे । इससे ज्यादा गंभीर और कौन सा मामला हो सकता हैं । आप देश के लोगों की, जो पिछड़े लोग हैं, उनकी आप मदद करना चाहते हैं, उनकी झुग्गियां बनाना चाहते हैं । हर पार्टी का आदमी यह कहता है कि हम गरीबों को आगे लाना चाहते हैं । मकान जलाएं जाएं, लोग जलाए जांएं, मासूमियत जलाई जाए और आप यह कहते हैं कि वक्त की बात है । इससे गंभीर मामला और क्या हो सकता है ? – आपसे पूछना चाहता हूं कि जब लोग जल रहे है तो यह कहां की हुकूमत है ? उस हूकूमत के वजीर को उस हुकूमत में रहने का कोई हक नहीं है, जो गरीबों पर हमला करे, गरीबों को लूटे । हमने मंदिर में बैठकर एक औरत को जब पूछा, उसका सारा जिस्म आग से जला हुआ था, मंदिर में मैंने उससे पूछा कि माता जी आप यह झूठ तो नहीं बोल रही हैं । उन्होंने कहा कि मैं सौगंध खाकर कहती हूं, मेरे जिस्म पर सलाखें लगाई गई हैं । मेरे सारे कपड़े फाड़ दिए गए हैं । वहां ऐसी-ऐसी बाते हो रही हैं । वाईस चेयरमैन साहब, इतना जुल्म कोई कैसे सह सकता हैं । ऐसा जुल्म कभी इतिहास में नहीं हुआ । वहां एक वजीर खड़ा हो, लोगों की झुग्गी में

श्री मोहिन्दर सिंह कल्याण : जाए और उनको जला दिया जाए । इसके लिए मैं अनॉरेबिल होम मिनिस्टर साहब से विनती करना चाहता हूं कि एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए । अगर आप जुडिशियल इंक्वायरी नहीं कराएंगे तो पानी का पानी साफ नहीं होगा । वहां ऐसे वजीर को जो गरीबों पर जुल्म कर रहा हैं उसको एक मिनट के लिए हुकूमत में रहने का कोई हक नहीं हैं । उसके लिए जुडिशियल इंक्वायरी की घोषणा होनी चाहिए । जयहिन्द ।

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, दलित और महिलाओं के उत्पीड़न के मामले आए दिन हम इस सदन में चिंतित करते हैं । सरकार किसी भी दल की हो और देश का कोई भी भाग हो महिलाओं और दलितों के उत्पीड़न आप तौर पर होते रहते हैं । मेर लायक दोस्तों ने तथ्यों को छिपा करके इसकी पृष्ठभूमि को प्रस्तुत नहीं किया । श्री माधव सिंह सोलंकी जी यहां बैठे है । मैं उनका ध्यान चाहूंगा । मोहिन्दर सिंह कल्याण जी ने 1981-82 का जिक्र किया । उस समय गुजरात में श्री माधव सिंह सोलंकी जी मुख्य मंत्री थे । इन्होंने पिछड़ी जातियों के आरक्षण की वृद्धि की घोषणा की थी । उसके विरोध में सारा गुजरात आरक्षण विरोधी आंदोलन में धू-धू करके जलने लगा और उस समय वह आरक्षण विरोध किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, उसी समय...(**व्यवधान**) माखन लाल फोतेदार जी सुनिए । आपकी पार्टी के एक एम०पी० श्री हीरालाल आर० परमार लोक सभा के सदस्य थे । उनकी फैक्टरी जलाई गई, उनकी गाड़ी जलाई गई, उनके बीस साल के लड़के को आग में झोंक दिया गया । जब उन्होंने यह मसला यहां उठाया तो कांग्रेस के एक एम०पी० ने उनका मुंह बंद कर दिया । तो यह पृष्ठभूमि हैं ।...(**व्यवधान**) मेरी भावना सुनिए, आपसे ज्यादा मुझे तकलीफ हैं । मैं कहना चाह रहा हूं ।..... (**व्यवधान**)

वहां पर एक पुरानी रंजिश चल रही है । दूसरे, वहां जो दलितों का मौहल्ला है इसमें कुछ लोग ऐसे हैं...(**व्यवधान**) मैं आपको सपोर्ट नहीं करुंगा, लेकिन मैं तथ्य पेश किया करता हूं, आप लोग राजनीति करते हैं ! तो मान्यवर इन लोगों में...(**व्यवधान**)

श्री अजीत जोगी : गौतम जी, हमने राजनीति की कोई बात नहीं की ।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) : आप इतनी-इतनी देर बोले हैं, उनको बोलने तो दीजिए ।...(**व्यवधान**)

श्री संघ प्रिय गौतम : उनमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनके घर जले हैं वे दादा टाईप के लोग हैं ।...(**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) : आप चेयर की तरफ बोलिए, उधर क्यों देख रहे हैं ।

श्री संघ प्रिय गौतम : मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि वह दादा टाईप के लोगों का पटेलों का बाजार है । यह पटेल वहां पर बहुत ताकतवर लोग हैं—पैसे से भी और राजनीतिक क्षेत्र में भी और उनका सारा मार्केट है । उनकी दुकान से सामान ले जाते हैं । होटल से खाना खाते हैं, पैसे नहीं देते और जब वह पैसे मांगते हैं तो झगड़ा होता है । पृष्ठभूमि यह है कि कुछ ऐसे ही लोगों की तलाश में लोग एक घर में गए और उन्होंने शक में एक घर में आग लगादी । लेकिन मेरा ऐतराज यह है कि कानून को कोई भी पटेल अपने हाथ में नहीं ले सकता । अगर वह बदमाश थे तो उन बदमाशों को पकडना चाहिए । घर में आग लगाने का हक किसी को भी नहीं है । फिर एक घर में आग लगाई तो 40 घरों में आग लगाने का हक किसी को हासिल नहीं है । इसलिए यह जो घर जलाए गए, यह गलत तरीके से जलाए गए हैं । यह एक अपराध हुआ है । मैं मांग करुंगा—जहां तक मिनिस्टर की बात हैं, कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं हैं । इसलिए

जब तक कोई जांच बिठा करके उस परिस्थिति की प्रमाणिकता न हो जाए, मंत्री के खिलाफ कोई आरोप नहीं लग सकता। ... **(व्यवधान)**

श्री अजीत जोगी : जिला कलेक्टर ने हमें बताया कि वहां मिनिस्टर थे। ... **(व्यवधान)**

श्री संघप्रिय गौतम : मान्यवर, मैं मांग करूंगा, नम्बर-1, इस पूरे प्रकरण की जांच की जाए। जितने घर जले हैं, एक-एक दो-दो लाख रुपये प्रत्येक परिवार को दिये जाएं। उनके लोगों को आजीविका दी जाए। जिन्होंने यह काम किया है, उनके खिलाफ फुर्तीदम दर्ज करके, चाहे मिनिस्टर ही क्यों न हो, हथकड़ी डाल करके जेल में बंद किया जाए और मान्यवर, जो लोग चले गए हैं, उन्हें बुला करके पुनर्वास कराया जाए, राजनीति न खेली जाए। धन्यवाद।

SHRI SANATAN BISI (Orissa): Thank you, Sir, for giving me this opportunity. It is a complete case of criminality and violence. Politics should not be involved so far as this matter is concerned. The second thing that I would like to say is that to grabe the landed property of the Harijans, Adivaasis and the Dalits this thing was perpetrated by the *goondas* and by those who are at the helm of affairs of the town. They wanted to grabe the property of the town because it would fetch them good money. They did not find any other way for getting this property and so they resorted to violence, arson and looting. Surprisingly enough, though there is the Criminal Procedure Code, the Indian Penal Code and various other laws, till now, no case has been instituted against the criminals, and the Dalits and the Harijans, are in the jail. The Home Minister who is also the Leader of the House is present here today and I take this opportunity and I request him through you to come forward with a statement. The Dalits and the Harijans who have been looted should be compensated and severe action should be taken against the criminals and those who are at the helm of affairs.

SHRI BALBIR SINGH (Punjab): Sir, I associate myself with this. Sir, it is not only the Dalits who have been hurt. But even we, the non-Dalits are hurt. The whole nation is ashamed of it. The whole House is ashamed of it. I appeal to the BJP that they should rise above party lines and they should ask for the dismissal of the Minister straightaway.

श्री राजूभाई ए० परमार (गुजरात) आदरणीय वाइस चेयरमैन सर, गुजरात के मेहसाना जिले के वड़ी टाउन में जो इंसिडेंट हुआ है और दलितों पर जो अत्याचार किए गए, उनको इनज्योर किया गया, उनकी दुकानें जला दी गई, उनके मकान जला दिए गए और चुन-चुन के उनकी जो लाइवलिहुड की जगहें थीं, उन सबको जला दिया गया और दलितों में एक भय का वातावरण क्रिएट कर दिया गया है। मैं भी इस हादसे के बाद वहां पर गया था। मैंने भी वहां पर सब देखा है और जो इनज्युर्ड हुए हैं, जो हॉस्पिटल में थे, उनसे मैंने बात की। उन्होंने क्लीयर कट ऐसा हमको बताया कि हमारे वड़ी टाउन के एम०एल०ए० और स्वास्थ्य मंत्री श्री नितिन भाई पटेल जब यह सब हो रहा था, उस टाइम पर वे वहां प्रेजेंट में। जो तुलसी भाई को मारा दुकानदारों ने, उसकी मदर ने जब मिनिस्टर नितिन भाई पटेल को ऐसा बोला कि आप अपने लोगों को समझाइए, एक तो आपने हमारे लड़के को मारा है, वह इनज्युर्ड है तो आप इन सबको समझाकर ले जाइए, उसकी माताजी ने मिनिस्टर को रिक्वेस्ट किया लेकिन उन्होंने गाली गलौज करके उनको भगा दिया और सबको बोले कि सबके मकान और दुकानें जला दो और

वहां पूरे चार घंटे तक यह सब होता रहा । पुलिस, पी०आई०बी० वहां थी, पी०एस०आई० भी वहां थी लेकिन कोई कार्यवाही किसी को रोकने की वहां पर नहीं की गई । जो लोग इनज्युर्ड हुए, हास्पिटल में ऐडमिट हुए, उनको कार्यवाही के बहाने पुलिस ने कस्टडी में डाल दिया। बिल्कुल एकतरफा कार्यवाही हुई है वहां पर । जिनका नुकसान हुआ हैं वे सब दलित हैं । जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई, वे सब भी दलित हैं तो इसके बारे में से आपसे खास गुजारिश करुंगा कि एक तो जब से गुजरात के अंदर तीन महीने से बी०जे०पी० के शासन आया है, गुजरात में भय, भ्रष्ट और भ्रष्टाचार, मुक्त शासन की बात करने वाले, बी०जे०पी० के शासन वाले ही पूरे गुजरात में भय का वातावरण क्रिएट कर रहे हैं अपने मंत्री के थ्रू । अभी दो-तीन दिन पहले गुजरात के अंदर, अहमदाबाद के अंदर दो दलित लोगों का मर्डर किया गया और कल भी पन्द्रह लोगों को इनज्योर किया गया । हमारे गुजरात में सचमुच में चार मुस्लिमों को पूरे गांव में मारा गया । जबसे यह सरकार वहां पर आयी है तबसे दलितों और मुसलमानो पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही है और बढ़ती जा रही हैं । मेरी आपके माध्यम से मांग है कि जो मिनिस्टर नितिन भाई पटेल वहां पर मौजूद थे, उनको सरकार से बरखास्त किया जाए, सरकार से हटा दिया जाए और जो इंजर्ड हुए हैं, इस मामले में भी गुजरात गवर्नमेंट बिल्कुल साइलेंट है, पुलिस साइलेंट है, ऐडमिनिस्ट्रेशन कुछ कार्यवाही नहीं कर रहा है । इसके बारे में मैं आपके माध्यम से और होम मिनिस्टर के माध्यम से मांग करूंगा कि इसकी जांच कराई जाए और हमारे मित्र लोग जो बोल रहे हैं कि इसमें कुछ हुआ नहीं है तो हम मांग करते हैं कि ज्यूडीशियल इन्क्वायरी हाई कोर्ट के सिटिंग जज के जरिए की जाए । इस प्रकार जो भी सच होगा वह पूरे हाऊस के सामने आ जाएगा और देश के सामने आ जाएगा । तो मैं आपके माध्यम से ज्यूडीशियल इन्क्वायरी की मांग करता हूं और जिनके घर जले हैं, जिनके मकान जल हैं और जो भी हुआ है, उनको जो मुआवजा दिया गया है, वह बहुत ही कम है । जो मुआवजे की रकम है, वह भी पूरी दी जाए । आपको जानकर ताज्जुब होगा कि दलितों की दुकानें, गल्ले आदि जहां-जहां थे, आज ऐडमिनिस्ट्रेशन ने वहां पर फेंसिंग कर दी है, वायर से फेंसिग कर दी है ताकि दुबारा वह लोग उधर न जा पाए और लोगों की जो चाल है, उसको दूसरी जगह शिफ्ट करके उनको अलग जगह देना चाहते हैं । मेरी आपसे मांग है कि जहां पर जिसकी दुकान थी, जहां पर जिसका गल्ला था, वहीं पर उसे बनाया जाए ।

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला चिमनभाई पटेल) : सर, मैं बहुत लम्बा चौड़ा लैक्चर नहीं देना चाहती हूं ...(**व्यवधान**)

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA (Uttar Pradesh): Mr. Vice-Chairman, a Minister never makes a speech, but only intervenes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): But she is a Member of this House.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: I have a point of order. Mrs. Patel is a Minister now. No doubt, she is a Member of this House, but she is a Minister now. The practice in this House is that in a debate, a Minister can only intervene. Never before had any Minister made a Special Mention. Therefore, my submission is that this new practice should not be allowed.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA (West Bengal): Sir, my point is, we are discussing the role of a particular Minister in a State Government and hon. Members may be rightly demanding that some action should be taken against that Minister. May be the Leader of the House will be responding to this. When this is the

situation, how can the Minister make a Special Mention? After all, she is a Minister. It is true that she is a Member of this House. But so long as she is in the Government, she cannot take part in this discussion. She can only speak on behalf of the Government. But she cannot speak in this House in her personal capacity. I object to this. Althaugh she is a Member of this House, she can speak only on behalf of the Government.

श्री दिग्विजय सिंह (बिहार) : उप-सभाध्यक्ष महोदय, मैडम एक सदस्या हैं, उनको बोलने का पूरा हक है लेकिन यह मंत्री भी हैं इसलिए वे इस बात का ख्याल रखें और जो अपनी बात कहे उन बातों का जो मतलब हो, उसको भी आप सही मायने में कार्यवाही के लिए प्रस्तुत करवाएं, यह मैं कहना चाहता हूं।

श्री चतुरानन मिश्र (बिहार) : यह अगर बोलेंगी तो अच्छी बात नहीं होगी।

श्रीमती निर्मिला चिमनभाई पटेल: अगर सभी सदस्यों को आपत्ति है तो मैं नहीं बोलूंगी पर आप सब लोग जानते हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूं। पूरा हाऊस इस बात से सहमत है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री चतुरानन मिश्र : हमें आपके साथ पूरी सहानुभूति है लेनिन सरकार होकर अगर आप बोलेंगी तो यह ठीक नहीं होगा।

श्री चिमनभाई मेहता : मैं जो कहना चाहता हूं, वह हकीकत भी है कि दलितों पर अत्याचार हुआ है, वह पीछे गये हैं उनके घर, उनकी दुकानें जलायी गयी हैं। हमलावरों को जेल नहीं भेजा गया है बल्कि जो हमले के विक्टिम बने, उनको जेल में भेजा गया है। यह सब बातें अगर हम दल के नजरिए से ने देखें तो मैं मानता हूं कि चाहे बी०जे०पी० हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, वे सभी दलितों की सहानुभूति में हैं। उसमें पालिटिक्स का कोई सवाल नहीं उठता और इसे पालिटिक्स का सवाल भी नहीं बनाना चाहिए। अगर पोलिटिसियन्स अपनी राय देंगे तो कुछ न कुछ डिफरेंसेज उसमें होंगे। इसलिए इसके लिए जूडीशियल इन्क्वायरी एक सही बात है। मेरा इस बारे में यह भी सुझाव है कि गुजरात के चीफ मिनिस्टर और अपोजीशन लीडर जो कांग्रेस मेन हैं, दोनों को किसी तटस्थ आदमी को ले जा करके वहां जाना चाहिए। तटस्थ आदमी इसलिए कि वह यथार्थ बात बता सके। अगर बी० जे०पी० और कांग्रेस के नेता किसी इम्पार्शियल आदमी को ले जा करके इन्क्वायरी के बारे प्राइमा-फेसी रिपोर्ट दे दें तो बाद में अगर डिफरेंस आफ ओपी-नियन होगा तो इसकी जूडीशियल इन्क्वा-यरी करा दें। मैं जानता हूं कि हर स्टेट में चाहे वहां जनता दल की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बी०जे० पी० की सरकार हो, शायद कम्युनिस्ट स्टेट्स को छोड़कर, हर जगह दलितों पर जुल्म होते रहे हैं। यह बात सही है इसके लिए हम सब दोषी हैं। पार्टियों की बात छोड़ दीजिए, इतना बड़ा गंभीर सवाल गुजरात में, जो गांधी जी का जन्मस्थल है वहां बन गया है। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी पार्टी का जिक्र करूं। रचनात्मक काम यही है कि इसकी जूडी-शियल इन्क्वायरी करा दें। लेकिन अगर अपोजीशन के लीडर, जो कांग्रेस पार्टी के हैं, वहां सरकार के लोगों के साथ जाए तो वहां पर एक एकता का वातावरण बनेगा। वरना जूडीशियल इन्क्वायरी ठीक है। वह अपनी जजमेंट दे देंगे लेकिन हम नहीं चाहने कि हमारे यहा, हमने देखा है कि गुजरात में कास्टिज्म पहले नहीं था लेकिन जब पोलिटिशियंस ने अपने हिसाब से बहुत कास्टिज्म बढ़ा दिया है। इस कास्टिज्म के कारण गुजरात में इस तरह के हालात पैदा हो गए हैं। इसके लिए जो प्रयास होने चाहिए वह नहीं हो रहे हैं। वैसे वहां की हालात और स्टेटों से ज्यादा अच्छी है। लेकिन इन सब चीजों को आप पोलिटिकल फायदे की दृष्टि से न देखें तो ठीक रहेगा। धन्यवाद।

SHRI S. JAIPAL REDDY (Andhra Pradesh): Sir, I deem it my painful duty to associate myself with the expressions of shock and grief over the incident that occurred. Mr. Jogi and his friends have visited the place. They have collected the facts scrupulously. I have no reason to disbelieve any fact narrated here. It is a measure of the degeneration that has come about in our times that these incidents should take place in the birthplace of Mahatma Gandhi. I do not want to point an accusing finger at any particular party. The fact remains that the B.J.P. is in power in Gujarat and there is a serious charge that one of the Ministers happened to be on the spot when this inhuman atrocity was perpetrated. And, now, what should any Government do? It may be true; it may not be true. He is certainly under a cloud. That Minister must go. If he doesn't go, he should be dropped. It is also clear from the narration of events that the local police was a passive witness, if not a partisan participant. Therefore, nobody will set any store by the impartial inquiry that may be conducted by the State Government.

Therefore, I plead that a CBI inquiry must be held into this and the Government of India cannot hold a CBI inquiry unless the State Government makes a request. That is also a problem. Therefore, if the B.J.P. Government would like to come clean, would like to lift itself out of this cloud it must offer itself for a CBI inquiry.

The State Government of Gujarat must write to the Government of India for asking the CBI to look into that. That is very important and deterrent punishment must be given. In fact we should have special courts to consider this matter. We saw in our own State, whenever these atrocities took place, the atrocities were followed up by huge voices of protests and then nothing followed. You must have special courts to try them because, I think these people who commit atrocities are not anything less than terrorists. They must be treated on the same footing as terrorists They must be tried in special courts and deterrent punishment mus be meted out.

SHRI GURU DAS DAS GUPTA: Sir, I am not for a CBI inquiry. I am for an open judicial trial. There should be open judicial proceedings. I demand open judicial proceedings by a court to be presided over by a Supreme Court judge. Considering the complexity of the issue, considering that a member of the Cabinet has been identified as a person who has instigated and incited the violent crowd, it is unlikely that justice will be done if the judicial process is led by somebody from there.

It should be done by a Supreme Court Judge and the proceedings should be open. I demand open proceedings because if the proceedings are open, that may act as an important factor in building up strong public opinion. Nothing in camera. This country must know. It is not only in the BJP States that these things are happening, our friends from this side and that side should know, the factor that the BJP Government is there, is only a minor additional point. The systematic attack on the Schedule Castes and the Scheduled Tribes had taken place in different States where different political parties had been ruling. The rulers belong to different political parties. Nobody can be absolved of the responsibility. I don't like to give the list.

Sir, the most important point is that the police was not a passive

participant, as my friend has said. It is quite true, but I should like to go a little forward. The law enforcement agency had colluded with the crime, they are also criminals. They not only failed to protect the lives, but they also did not respond to the request of the hospital authorities to record statements, which means the police is there to suppress the facts; the police is there to guard, to protect the criminals. Therefore, they are the colluders. The crime had been done by somebody else and the people who were there to book the criminals had also committed the crime by becoming colluders. This is the level of degeneration. And I may tell you that this is happening with the police in many places, in Bombay riots, in Haryana riots, in Moradabad, Uttar Pradesh, everywhere we have found the police to be the worst criminals in the way they have colluded. Therefore, something has to be done to inflict exemplary punishment on the law enforcement agency. It is not enought to say that the Chief Minister along with the leader of the Opposition should go. No, something concrete should be done to tell the administration, thus far and no further.

There is not going to be a further toleration of the act of collusion and that message can go if a judicial inquiry is done, presided over by a Supreme Court judge and if the proceedings are thrown open to let the whole country know. Sir, the most shameful part of the story is that the politcal leader, who is there in the Government, has been found to be inciting the crowd. It is another worst part. I do not know if the story is one-sided. I do not know if their claim is justified. But, the very fact that there is a complaint, there is a clamour, that should be the sufficient prima facie ground for the hon. Chief Minister of Gujarat to throw hm out. There should be a judicial inquiry and pending the inquiry, the man must be out of the Cabinet because his presence will definitely influence the process of judical investigation. To make the judicial investigation fool-proof.. .. (Time Bell rings) .. that man must be out of the Government.

Thirdly, Sir, I am suggesting one thing to this House. I do not know the methodology as to how the Gujarat Government may be pursuaded to accept such a judicial inquiry. But I think the hon. Minister for Home and the Leader of the House, a very honoured and veteran politican, should say something here on the floor of the House, and he should not say, "we are looking for the report" because know the way in which the Ministers generally respond. So let him make a statement that the situation demands a judicial inquiry. It is up to the wisdom of the Government to declare it. Let there be a public opinion, a sort of pressure on them also. It should not be just a formal discussion in the House. I expect that from him. I appeal to the political leadership of the Bharatiya Janata Party, which always boasts of high standards in public life—many of the leaders have been saying this in the open—let them also set an example by excluding this gentleman from the Cabinet Let them set an example for the others. If they do it, they can demand the same when some such complaints are raised against other Governents also. Let the political eladership of the Bharatiya Janata Party take the step.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Please conclude.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: ...by asking the Minister to be out of the Government pending the judicial inquiry.

SHRI TINDIVANAM G. VENKATRAMAN (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, I join hands with all the hon. Members who have condemned the atrocities on *Harijans* which took place on the 12th of May, at Kadi village of Gujarat. Sir, it has become a regular feature in all the States to commit atrocities on the lower strata of society and the SC/STs. Sir, the most atrocious thing in this incident is that a responsible Minister has taken part in it and he is still at large. What the law is doing there when it has been found that this man, this particular gentleman, who is a Minister of a particular Department was present there and was inciting and abetting the people? He must be the first accused in this case. Therefore, the law is a mute observer there. According to the statements taken by the two parliamentarians, who went there, this is the individual who collected the patels there, who are very powerful persons. The poor people have been victimised there. Their homes have been burrent down. Nearly one hundred persons have been injured. There is a loss of property of about Rs. 40 lakhs.

Sir, incidentally, I may quote one incident that took place in Tamil Nadu. In a village of Tamil Nadu, the people wanted to instal a statue of Ambedkar. Sir, as per the records the whole land of that village is *Panchami* land. *Panchami* land means the land which is allotted to the SC/STs. One powerful police officials... (*Interruptions*)...

SHRI S. MUTHU MANIA (Tamil Nadu): Sir, he is misleading the House... (*Interruptions*)...

1 P.M.

SHRI TINDIVANAM G. VENKATRAMAN: Sir, the whole mischief was done by a top official and he was having a piece of land and the Harijans are having that land. They have located that particular Ambedkar statue installed there. The Ambedkar statue was taken away by persons who are influential in the Government. Therefore, ... (*Interruptions*)...

SHRI S. MUTHU MANI: Everything has been settled

SHRI TINDIVANAM G. VENKATRAMAN: What is settled? It has not been settled.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): This incident took place in a district in Gujarat

SHRI TINDIVANAM G. VENKATRAMAN: No, no. I am telling you as a whole. Do not take only one part of it. You are taking only Gujarat. Tamil Nadu is also in India. Therefore, what has happened is under the influence of the top officials, these people removed the Ambedkar statue. People there wanted to go and get back the statue. Then, what happened was, there was police lathi-charge, three lives have been lost and properties have been lost. So, after the interference of these persons hey have come to terms now. Therfore, it has become a routine affair and the police officials are only siding with them and they look after interests of the Government only. Who is there behind the mischief? If there is a minister there, law will not speak. They will be mute observers. They will become almost co-accused. Therefore, that is the trend and it must be curbed at any rate. As my friend says, I am not putting it on a political ground. I am telling you, in a broader sense that it must be curbed, and there is no point in preaching 'Sermon on the Mount'. You must practise it.

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे : उप-सभाध्यक्ष महोदय, यहां गुजरात के कड़ी विलेज की जिस घटना की बात यहां कही गयी है, मैं राजनीति से ऊपर उठकर बात करना चाहता हूं मैं कोई राजनीति की बात नहीं करना चाहता हूं, जो सत्य घटना हुई है, उसका ब्यान या उसका ब्यौरा यहां नहीं दिया गया है ।

महोदय, मैं पहले यह कहना चाहता हूं कि कड़ी में जो कुछ घटना घटी, वह बिल्कुल अनफार्चुनेट है, यह मैं मानता हूं । ऐसा बनाव इस देश में नहीं बनना चाहिए, लेकिन इसके पीछे जो बात हुई कड़ी विलेज में, जहां कि यह घटना घटी, वहां आज से कई साल पहले जो लोग वहां रहते हैं, वह दलितों, एंटी-सोशल और व्यापारी के बीच हुई घटना है । कई सालों से वह व्यापारी के पास से पैसा ले जाते थे, माल ले जाते थे फिर पैसा नहीं देते थे और जो उनके साथ कोई व्यवहार कर दिया तो गाली-गलौच करते थे, उनके खिलाफ एट्रोसिटीज की फरियाद दाखिल करते थे । ऐसे कई केसेज व्यापारियों के खिलाफ एट्रोसिटी के कड़ी में हुए हैं । व्यापारियों के खिलाफ हुए हैं । . . . (**व्यवधान**) . . .पहले सुन लीजिए जोगीजी, परमार जी आप सुन लीजिए . . . . . (**व्यवधान**) . . .

श्री अजीत जोगी : यह बात सही है तो भी उसका घर तो नहीं जला सकते आप. . . . (**व्यवधान**)

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे : आप सुन लीजिए, मैं कोई फेवर नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनकी हिस्ट्री जानिए, वहां जो 5–6 मार्फिया हैं, कमनसीब से वह दलित हैं । वहां कई दिनों से यह बात चलती थी । व्यापारी के पास माल लेने गए. . . (**व्यवधान**) .लेकिन उनको पैसा नहीं दिया, किसी व्यापारी ने कहा कि भाई हमारा माल वापिस दे दो मुझे नहीं बेचना, वहीं से यह बात शुरू हुई और आप जो कह रहे हैं कि मिनिस्टर वहां थे, मिनिस्टर जब हल्ला-गुल्ला हुआ तब वहां नहीं थे . . . (**व्यवधान**) . . .

श्री अजीत जोगी : कलेक्टर की रिपोर्ट में कहा गया है कि मिनिस्टर वहां थे ।

SHRI RAJUBHAI A. PARMAR: We got the affidavit of the injured persons which says that the Minister was present.

SHRI AJIT P. K. JOGI: The Minister was present. (*Interruptions*)

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे : आप पहले सुन लीजिए, मैं क्या कह रहा हूं । (**व्यवधान**) आप सुनिए तो सही । (**व्यवधान**) . . .

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) : प्लीज, आप उन्हें बोलने दें उनकी बात ।

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे : वह जो मिनिस्टर हैं, वह उसी गांव के हैं । व्यापारी लोग उनके पास गए कि भाई, ऐसे कुछ हमारे यहां घटना हो गई है बाजार में । उन्होंने उनको समझाया । . . (**व्यवधान**) . . .कमनसीबी से वह उसी दिन गांव में थे, लेकिन वहां नहीं थे वह, जैसा आप कह रहे हैं कि मिनिस्टर साहब लोगों को हल्ला-गुल्ला करने के लिए कह रहे थे । ऐसी कोई बात नहीं हुई है। ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। . . . . . (**व्यवधान**) . . .और आगे सुनिए ।

श्री अजीत जोगी : आप गलत मत बोलिए ।

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे : आगे सुनिए । वहां सवर्ण की दुकान भी जली है, माइनोरिटि की दुकान भी जली हुई है और एक ही मकान जला है । गुजरात सरकार ने 2,000/– रुपया उन सब लोगों को दिया है ।

श्री मोहिन्दर सिंह कल्याण: नहीं दिया। किसी को नहीं दिया ।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) : कल्याण जी, आप बैठिए ।

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे : अरे, आपकी रिपोर्ट पढ़ो । आपकी रिपोर्ट हमारे पास है । जोगी जी से आप पूछिए। वहां 3.68 लाख रुपया दिया है, ऐसा जोगी जी ने कहा है । ... **(व्यवधान)**.... आप पहले पढ़िए । और, और सुनिए । दोनों के खिलाफ पुलिस स्टेशन में फरियाद हुई है । यहां से 16 लोग व्यापारियों में से भी पकड़ गए हैं और एंटी सोशल जो हैं वह भी पकड़े गए हैं ।

श्री राजूभाई ए. परमार : सर, कोई 16 लोग व्यापारियों में से नहीं पकड़े, किसी व्यापारी को नहीं पकड़ा । वहां जो पकड़े हैं... **(व्यवधान)**...आप गलत बात कर रहे हैं । आप नाम बताइए, किसको पकड़ा है ।

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे : 16 व्यापारी पकड़े हैं । एंटी सोशल लोग भी पकड़े गए हैं ।

श्री अजीत जोगी : दवे जी, इसमें राजनीति मत लाइए । आपने बहुत अच्छा शरू किया था, अब इसमें राजनीति मत लाइए ।

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे : गुजरात सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही कर रही है । ... **(व्यवधान)**...उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह कह रहा हूं कि ऐसी घटनाएं ...**(व्यवधान)**..

श्री राजूभाई ए० परमार : जो लोग बाबूलाल ए , वे लोग नाम ले रहे हैं कि इस आदमी ने मारा है, उसको क्यों नहीं पकड़ते हैं ? आप बताइए ।

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे : ऐसी घटना आगे न बने, इसके लिए गुजरात सरकार चिंतित है । वहां भी जिन लोगों को हेल्प करनी थी, गुजरात सरकार के प्रतिनिधि वहां गए थे, सब लोगों से मिल थे, व्यापारियों को भी मिल और जिन जिन लोगों के खिलाफ कार्यवाही वहां करनी थी, वह कार्यवाही वहां चल रही है ।

श्री राजूभाई ए० परमार : व्यापारियों से ही मिले यह लोग । ...**(व्यवधान)**...

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे : जो बाजार में व्यापारी थे, उनकी एक दुकान जली है, एक माइनोरिटी की दुकान जली है ।

श्री अजीत जोगी : बीच में दुकान ऐसी होगी, इसलिए जली ।

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे : लेकिन, मिनिस्टर का हाजिर रहना, यह कहना गलत बात है। उस दिन वह गांव में थे, जरूर गांव में थे, व्यापारी लोग उनको मिलने भी गए थे कि भाई, एंटी सोशल लोग हमें परेशान कर रहे हैं, कुछ करिए। उन्होंने उनको समझाया कि भाई, ऐसा झगड़ा मत करिए, ऐसा मत करिए । यह जो घटना कड़ी में घटी है, गुजरात सरकार उसमें कड़ी कार्यवाही कर रही है, इतना ही मेरा कहना है ।

विपक्ष के नेता (श्री सिकन्दर बख्त) : सदर साहब, मैं आमतौर पर कोशिश करता हूं कि जब इस सदन में कुछ कहूं तो किसी भी वाक्ये से मुतालिक फैक्ट्स इकट्ठा कर लूं और उसके बाद रखूं। जोगी साहब, मुझे लगता है, अपनी जाती वाकफियत की बिना पर बोले हैं । उनको बोलने का हक था । मैं कोई जाती वाकफियत नहीं रखता, जाती तौर पर मैंने कोई तफतीश भी नही की है । आज यह वाक्या हुआ है, करूंगा जरूर तफतीश । यह वाक्या बहुत अफसोसनाक है, तकलीफदेह है । मेरे साथी दवे साहब गुजरात से आए हैं । मैं इंतजार कर रहा था कि वह कुछ कहें । मुझे खुशी है, उन्होंने इस चीज को तसलीम किया, इस वाक्ये की मजम्मत की और अफसोस का इजहार किया । किस किस्म का एक्शन, यह मुझे

[श्री सिकन्दर बख्त]

बताया गया अभी, कि चीफ मिनिस्टर साहब वहां गए हैं, देख रहे हैं कि क्या कार्यवाही करें । लेकिन, कार्यवाही सरकार जो करती है, उसका इंतजार तो जरूर करना चाहिए । हो सकता है कि पुलिस वालों की गल्तियां, जैसा आपने बताया कि वह मौजूद थे, गल्तियां रही हो, लेकिन सरकार क्या कदम उठा रही है, वह भरपूर कदम है या नही, उसमें तब भी कमी रहती है तब कुछ कहना चाहिए, लेकिन अहकमाक साबित नहीं करना चाहिए यहां । यह जो दूसरे किस्म के कि उनके हुक्म से गुजरात की सरकार चलेगी, वह बुनियादी तौर पर दुरस्त बात नहीं है । उसका इंतजार कीजिए कि सरकार वहां क्या कर रही है और करना चाहिए । हादसा ऐसा है जिस पर सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, मैं समझता हूं । अगर यह सवाल दोबारा उठा तो दोबारा मैं अपनी जाती तहकीकात और तफतीश करने के बाद हाजिर होऊंगा और फिर कोई और बात कहूंगा । दोहराना चाहता हूं कि हादसा अफसोसनाक है, दर्दनाक है, सरकार को मुनासिब कार्रवाई करनी चाहिए ।

दूसरी दरख्वास्त मेरी यह है कि हमको खाली बातें सुनकर एहकामात सादिर करने की आदत छोड़ देनी चाहिए ।

†[दूसरी दरख्वास्त मेरी यह है कि हमको खाली बातें सुनकर एहकामात सादिर करने की आदत छोड़ देनी चाहिए ।]: सभापति महोदय, मैं आम तौर पर कोशिश करता हूं कि जब इस सदन में कुछ कहूं तो किसी भी वाकये से मुताल्लिक फैक्ट्स इकट्ठा करूं और उसके बाद कहूं । जो मैं साहब मुझे लगता है कि अपनी जाती वाकफियत की बुनियाद पर बोलता हूं । उनको बोलने का हक था । मैं कोई जाती वाकफियत

नहीं रखता । जाती तौर पर मैंने कोई तफतीश भी नहीं की है । आज यह वाकया हुआ है । करूंगा जरूर तफतीश । यह वाकया बहुत अफसोसनाक है । तकलीफदेह है । मेरे साथी दो मेम्बर साहब गुजरात से आए हैं । मैं इंतजार कर रहा था कि वह कुछ कहें । मुझे खुशी है कि उन्होंने इसे तसलीम किया । इस वाकये की मजम्मत की और अफसोस का इजहार किया । किस किस्म का एक्शन । यह मुझे बताया गया अभी कि चीफ मिनिस्टर साहब वहां गए हैं । देख रहे हैं कि वहां क्या कार्रवाई करें । लेकिन कार्रवाई सरकार जो करती है उसका इंतजार तो जरूर करना चाहिए । हो सकता है कि पुलिस वालों की गल्तियां । जैसा आपने बताया कि वह मौजूद थे । गल्तियां रही हों । लेकिन सरकार क्या कदम उठा रही है, वह भरपूर कदम है या नहीं, उसमें तब भी कमी रहती है तब कुछ कहना चाहिए । लेकिन अहकमाक साबित नहीं करना चाहिए यहां । यह जो दूसरे किस्म के कि उनके हुक्म से गुजरात की सरकार चलेगी । वह बुनियादी तौर पर दुरस्त बात नहीं है । उसका इंतजार कीजिए कि सरकार वहां क्या कर रही है और करना चाहिए । हादसा ऐसा है जिस पर सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए । मैं समझता हूं । अगर यह सवाल दोबारा उठा तो दोबारा मैं अपनी जाती तहकीकात और तफतीश करने के बाद हाजिर होऊंगा और फिर कोई और बात कहूंगा । दोहराना चाहता हूं कि हादसा अफसोसनाक है । दर्दनाक है । सरकार को मुनासिब कार्रवाई करनी चाहिए ।

कुछ कहना चाहिए लेकिन एहकामात सादिर नहीं करने चाहिए यहां । यह जो दूसरे किस्म के कि उनके हुक्म से गुजरात की सरकार चलेगी । वह बुनियादी तौर पर दुरस्त बात नहीं है । उसका इंतजार कीजिए कि सरकार वहां क्या कर रही है और करना चाहिए । हादसा ऐसा है जिस पर सरकार

†[ ]Transilteration in Arabic Script

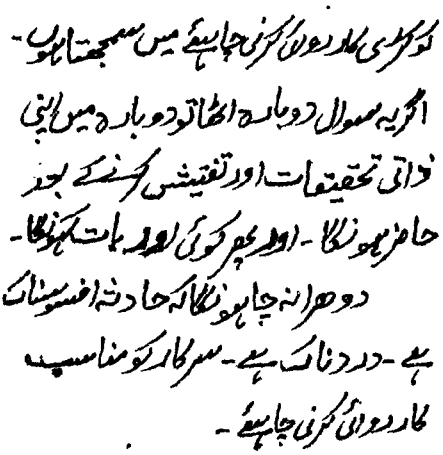

دوسری درخواست میری یہ ہے
کہ ہم کو خالی باتیں بس کر احکامات صادر
کرنے کی عادت چھوڑ دینی چاہیئے۔
"ختم شد"

श्रीमती सरसा माहेश्वरी (पश्चिमी बंगाल) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे सम्माननीय नेता सिकन्दर बख्त साहब ने कहा कि वे घटना के तमाम तथ्यों की पड़ताल करने के बाद ही कुछ कहना चाहते हैं । उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं भी सिर्फ यही कहना चाहती हूं कि :—

"बात बोलेगी, हम नहीं,
भेद खोलेगी बात"

उपसभाध्यक्ष महोदय, बात यह है, इतिहास यह है कि हमेशा-हमेशा से हमारे समाज में दलितों पर, शोषितों पर, वंचितों पर अत्याचार होते रहे हैं । इस विशेष घटना में तथ्यों की कुछ भी हेरा-फेरी हो, तथ्यों की गलतबयानी हो, मैं इसके बारे में नहीं चाहती लेकिन मैं इतना जरूरी कहना चाहूंगी कि यह हमारे समाज का वह क्रूर नग्न यथार्थ है, जिस क्रूर नग्न यथार्थ को एक बार फिर जोगी जी ने हमारी आंखों में आखें डालकर बताया है कि हमारे समाज के दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित लोग सामाजिक न्याय की परिधि से कितनी दूर है । संविधान में उल्लिखित निर्देशक कानन के सामने सब समान हैं, विधि के सामने सब समान है, यह कितनी खोखली बातें है, यथार्थ से इनका नाता कितनी दूर का है । इसलिए, उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं कि जब इस तरह की घटनाएं घटती है, हमारे माननीय सांसद शायद ईमानदारी से कहते हैं कि हम राजनीति नहीं कर रहे । मैं यह कहना चाहती हूं कि हम राजनीति आखिर किसलिए कर रहे हैं ? क्या राजनीति हम दलितों को ऊपर उठाने के लिए नहीं कर रहे हैं ? क्या राजनीति हम शोषितों को ऊपर उठाने के लिए नहीं कर रहे हैं ? क्या राजनीति हम समाज में न्याय की स्थापना करने के लिए नहीं कर रहे हैं ? राजनीति का आखिर उद्देश्य क्या है ? इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि अगर कोई ऐसी राजनीति हो जो सिर्फ प्रभुत्व-शाली लोगों का सम्मान समाज में बढ़ाती हैं, अगर कोई ऐसी राजनीति है जो दलितों पर अत्याचार करती है, अगर कोई ऐसी राजनीति है जो समाज में जातिवाद बढ़ाती है, अगर कोई ऐसी राजनीति है जो समाज में धर्मांधता बढ़ाती है, अगर कोई ऐसी राजनीति है जो समाज में साम्प्रदायिकता फैलाती है, जो समाज में विद्वेष खड़ा करती है, जो समाज में आदमी और आदमी के बीच में दीवारें खड़ी करती है, ऐसी राजनीति को जरूर चिन्हित करना चाहिए, ऐसी राजनीति को जरूर पहचानना चाहिए और ऐसे राजनेताओं को जनता के कटघरे में खड़ा करके कहना चाहिए कि बताइए आपकी राजनीति क्या है । मुक्ती बोध ने जैसे कहा था, बताइए पार्टनर तुम्हारी राज-नीति क्या है, मैं यह कहना चाहती हूं कि बताइए पार्टनर तुम्हारी राजनीति क्या है, यह कहना चाहती हूं कि

Transliteration in Arabic script.

बताए पार्टनर तुम्हारी राजनीति क्या है, आप किसके पक्षधर हैं? मैं तो यह कहना चाहती हूं कि मैं दलितों की पक्षधर हूं, शोषितों की, पीड़ितों की पक्षधर हूं, यह कम्यूनिस्ट राजनीति है और यह राजनीति म करती हूं और मुझ कोई गिला या शिकवा नहीं है यही राजनीति का मेरा उद्देश्य है । इसलिए, उप-सभाध्यक्ष महोदय, मैं इस विशेष घटना के संदर्भ में यह कहना चाहती हूं कि अगर हम वास्तव में चाहते हैं कि हमारे समाज में जो यह अन्याय हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, शोषण हो रहे हैं, इन पर लगाम लगे तो, एक विशेष घटना को लेकर हम संसद में आएं और सिर्फ प्रलाप करके अपने दायित्व की इतिश्री कर लें, यह सिलसिला अब नहीं चल सकेगा । इस सिलसिले को खत्म करना चाहिए और यह सिलसिला तभी खत्म होगा, जब हम लोग जो राजनीति करते हैं, उनको यह निर्णय लेना होगा कि हमारी राजनीति कहां गलत है क्योंकि समाज में इससे असमानता की लकीरें खिचती चली जा रही हैं ।

इसलिए, उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इस विशेष घटना के संदर्भ में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि इस घटना की जांच होनी चाहिए और अगर पुलिस और प्रशासन में बैठे हुए लोग, अगर राज-नीति में बैठे हुए लोग, अगर संविधान की शपथ लिया हुआ कोई मंत्री अपने दायित्व क्षेत्रों का, अपने उत्तरदायित्वों का उल्लंघन करता है तो मैं समझती हूं कि राजनीति के सामने यह सबसे बड़ी चुनौती है और राजनीति अगर इस चुनौती का सही जवाब नहीं दे पाएगी तो मैं समझती हूं कि हमारे तमाम तर्क, हमारे तमाम वादविवाद का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा । हम सिर्फ यहां प्रलाप करते रहेंगे और हमारी जनता पर अत्याचार होते रहेंगे । और हमारी जनता पर अत्याचार होते रहेंगे । इसलिए इस निरर्थक प्रलाप को बंद करना चाहिए और हमें समस्या की जड़ों को समझते हुए सही कदम उठाने चाहिए और विशेष घटना की जांच करके आप एक मिसाल स्थापित करिए और बताइए कि आपकी राजनीति क्या है । धन्यवाद ।

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मोम अफजल (उत्तर प्रदेश) : वाईस चेयरमैन साहब, गुजरात की दो बातें अहम है । पहली बात तो गुजरात में गांधी जी की पदायश हुई और माना गया कि यह गांधी जी की सरजमी है । दूसरी बात मने जो गुजरात में जाकर महसूस की, वह यह है कि गुजरातियों के नाम के आगे और बोलचाल में हमेशा भाई और बेन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है । जब तक वह नाम के आगे भाई और बेन नहीं इस्तेमाल कर लेते तो बातचीत नहीं होती । यह दो बातें वहां अहम है । लकिन वहां के माहौल के मुताल्लिक भी दो अहम बातें मैं आपको बताना चाहता हूं । कम्युनल राइट की हिस्ट्री में अगर कोई इंसान जिंदा जलाया गया तो यह गुजरात के अहमदाबाद में जलाया गया था दूसरी अहम बात यह है कि पिछली सरकार के दौरान अगर सबसे ज्यादा लोग टाडा जैसे कानून में कहीं पकड़े गए तो वह भी गुजरात में ही पकड़े गए है। ....(**व्यवधान**)

सर, मैं बुनायादी सवाल उठा रहा हूं । इसलिए अभी जो सरला जी ने बात उठाई और इससे चिमनभाई मेहता साहब ने बात उठाई, मैं उधर जाना चाहता हुं। म समझता हूं कि गुरूदास साहब ने जो ओपन जुडिशियल इंक्वायरी की बात की है, मैं उससे सहमत हूं । मामला पचास पैसे का था, बढ़ करके पिटाई तक आया। उसके बाद पूरी दलित बस्ती के ऊपर हमला हो गया । मिनिस्टर की मौजूदगी में हुआ । मैं यह नहीं समझता, अभी मैंने संघ प्रिय गौतम साहब की भी तकरीर सुनी और मैं नहीं समझता कि कोई बी.जे.पी. की साईड से खड़े होकर के वाक्ये को डिफेंस कर सकता है । अगर करेगा तो बहुत शर्मनाक बात होगी । लीडर आफ दि आपोजीशन ने भी अपनी बात कही है । इसके बाद इस वाक्यों पर बहुत ज्यादा कहने की गुंजायश नहीं

[श्री मोहम्मद अफजल उर्फ भीम अफजल]

है । मिनिस्टर को तो हटाना ही चाहिए। लेकिन बुनियादी बात यह है कि इस पूरे वाक्ये में मैं यह देख रहा हूं कि पौलिटिकल आदमी को भी गाली पड़ रही है । लेकिन एक पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जिसको गुरूदास साहब ने इशारातन कहा, म यह कहता हूं कि आज गुजरात का जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है जिसके अंदर ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है और जिसके अंदर पुलिस भी शामिल है, उसका रवैया क्या है ? जरा सा पौलिटिकल इशारा होता है तो वह आगे बढ़ करके उससे कहीं ज्यादा वह कारनेज करने का काम करते है, उससे ज्यादा जुल्म करने का काम करते है । तो खाली सवाल यह नहीं है कि मिनिस्टर को हटा दिया जाएगा तो मसला हल हो जाएगा । गुजरात की हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए पिछले दस साल के अंदर गुजरात म क्या हुआ है । 1983 मे कम्युनल राइट हुआ था। उसके वाक्या मुझे आज तक याद है । जो कम्युनल राइट होते रहे है उनका मुझको पर्सनल अनुभव रहा है । चूंकि एज जर्नलिस्ट ऐसी जगहों पर गया हूं और वहां जाकर के मैंने देखा है । दूसरी बात म यह कहना चाहता हूं कि मुझको कोई ऐतराज नहीं है इसको कहने में । मैं एक मायनोरिटी के फिरके से आया हूं और गुजरात के बहुत से इलाकों मे भी गया हूं– इलैक्शन में भी और उसके बाद मैं भी। पता नहीं क्यों वहां ऐसा माहौल है, थोड़ा सा छुआछात का माहौल अभी मौजूद है । हालांकि गांधी जी ने सबसे ज्यादा जो लड़ाई लड़ी वह छुआछात के खिलाफ लड़ी और आज उसी सरजमीं पर लोग छुआछात की बात ज्यादा करें तो अफसोस की बात है । तो खाली मामला एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं है और वजीरे दाखला साहब का एक्शन लेने का भी नहीं है ! यहां सोलंकी साहब बैठे हुए थे, वह चले गए । श्रीमती पटेल भी बैठी हुई थी, वह भी चली गई। दूसरे हमारे गुजरात के अहम लीडर बैठे हुए हैं । मैं तो यह कहना चाहता हूं कि आपको खुद गुजरात की सरजमी पर जो कम्युनल टेंशन पिछले दस साल के अंदर बढ़ा है और जो जातिवाद की नफरत बढ़ी है उसको चैक करने के लिए कोई न कोई तरीका ढुंढना चाहिए । मेरा यह माननां है कि पौलिटिकल लोग बहुत जगहों पर जिम्मेदार है । लेकिन एक वह वाक्या–(घंटी)–उसको आमतौर पर नजर अंदाज करते हैं, वह है–ब्यूरोक्रेसी । आज ब्यूरोक्रेसी मुल्क के अंदर किस तरह से कर रही है, अभी वजीरे दाखला साहब ने चीफ मिनिस्टर्स की चार तारीख को मीटिंग की थी । उसमें अपनी एक रिपोर्ट पेश की थी। उसमें तीन स्टेट से रिपोर्ट आई कि अगर टाडा जारी रहता है तो हमे कोई ऐतराज नहीं है और उन तीनों स्टेट्स के अंदर जब चीफ मिनिस्टर के बयानात आए तो उन्होंने कहा कि टाडा के बिल्कुल खिलाफ हैं । अंदर जाकर देखा कि ब्यूरोक्रट ने अपनी रिपोर्ट तैयार करके सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसकी रिपोर्ट बनाकर भेज दी, वह भी ब्यूरोक्रेट के हाथों । आप कब तक इस मुल्क को ब्यूरोक्रेटस के हाथों इस तरह से चलाते रहेंगे ? जब सियासी लोग अपने तौर पर नाकाम होते है तो नीचे के लोग उनसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करगे । कोई चैक नहीं है आज ब्यूरोक्रेसी के ऊपर ! कौन सा चैक है इस पार्लियामेंट के अंदर ? इस पार्लियामेंट के अदर अगर मैं कोई नाम लेता हूं तो सर, आपकी चेयर से आदेश होता है कि जो आदमी अपने आपको डिफेंस नहीं कर सकता, उसका नाम नहीं लिया जा सकता । हम लोगों की कंस्टीट्युएंसी है । हम लोग पांच साल, छः साल के बाद अवाम के सामने जवाब दे लेकिन वह सरकारी मुलाजिम जो एक बार आई.ए.एस. का इम्तिहान पास करके आ गया, उसकी जवाबदेही कितनी है अलावा इसके कि उसका ट्रांसफर हो जाता है । अगर पुलिस और ऐडमिनिस्ट्रेशन में खराबी है तो आपको इस जांच को भी देखना पड़ेगा । मैं यह मानता हूं गाली देने का बड़ा रिवाज है हमारे यहां पोलिटिकल लोगों को ।

यहां एक मिनिस्टर इनवाल्व है, वाकायदा इनक्वायरी होनी चाहिए थी लेकिन ऐड-मिनिस्ट्रेशन को हिदायत, ऐक्जीक्यूटिव को यह पाबंदी है कि अगर कोई पोलिटिकल आदमी उसको गलत हुकम देता है तो उसको मानने से इंकार कर दे । क्यों पुलिस ने उसके कहने से ऐसा किया ? क्यों पुलिस ने ऐसा नहीं किया कि अगर मिनिस्टर वहां खड़ा हुआ था तो कोई कार्यवाही नहीं की ? इसलिए पुलिस के लोग भी जिम्मेदार है । इसलिए इनक्वा-यरी जब हो तो इन सारे आस्पेक्टस को देखना चाहिए और बुनियादी जो मसला है गुजरात में उस पर हम सभी को ध्यान देना चाहिए । बहुत बहुत शुक्रिया ।

†الشری محمد افضل عرف م۔ افضل

"اتر پردیش": وائس چیئرمین صاحب۔ گجرات کی دو باتیں اہم ہیں۔ پہلی بات تو گجرات میں گاندھی جی پیدائش ہوئی اور مانا گیا کہ یہ گاندھی جی کی سرزمین ہے۔ دوسری بات میں نے گجرات میں جاکر محسوس کی وہ یہ ہے کہ گجراتیوں کے نام کے آگے اور بول چال میں ہمیشہ بھائی اور بین کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جب تک وہ نام کے آگے بھائی اور بین نہیں استعمال کر لیتے تو بات چیت نہیں ہوتی۔ یہ دو باتیں اہم ہیں لیکن وہاں کے ماحول کے متعلق بھی دو اہم باتیں میں آپکو بتانا چاہتا ہوں۔ کمیونل رائٹ کی حصہ داری میں اگر کوئی انسان

زندہ جلا دیا گیا تو گجرات کے احمد آباد میں جلا دیا گیا تھا۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ پچھلی سرکار کے دوران اگر سب سے زیادہ لوگ "ٹاڈا" جیسے قانون میں کہیں پکڑے گئے تو وہ بھی گجرات میں ہی پکڑے گئے ہیں ... "مداخلت" ...

سر میں بنیادی سوال اٹھا رہا ہوں۔ اسلئے ابھی جو سرلا جی نے بات اٹھائی اور اس سے چمن بھائی مہتا صاحب نے بات اٹھائی۔ میں ادھر جانا چاہتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ گرو داس صاحب نے جو اوپن چیوڈیشیل انکوائری کی بات کی ہے میں اس سے سہمت ہوں۔ معاملہ پچاس پیسے کا تھا۔ بڑھکر پٹائی تک آیا۔ اسکے بعد پوری دلت بستی کے اوپر حملہ ہوگیا۔ منسٹر کی موجودگی میں ہوا۔ میں یہ نہیں سمجھتا۔ ابھی میں نے سنگھ پریوار کے تم صاحب کی تقریر سنی اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بی جے۔ پی کی سائیڈ سے کھڑے ہو کر واقعے کو ڈیفینس کر سکتا ہے۔ اگر کریگا تو بہت شرمناک بات ہوگی لیڈر آف دی اپوزیشن نے بھی اپنی بات کہی ہے۔ اسکے بعد اس واقعے پر بہت زیادہ کہنے کی گنجائش نہیں ہے۔ منسٹر کو تو ہٹانا ہی چاہیئے۔ لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ اس

†[ ]Transilteration in Arabic Script

سارے علاقے میں بھی گیا ہوں - الیکشن میں بھی اور اسکے بعد بھی - پتہ نہیں وہاں کیوں ایسا ماحول ہے - تھوڑا سا چھوا چھوت کا ماحول ابھی موجود ہے - حالانکہ گاندھی جی نے جو لڑائی لڑی وہ چھوا چھوت کے خلاف لڑی اور آج اسی سرزمین پر لوگ چھوا چھوت کی بات زیادہ کریں تو افسوس کی بات ہے - تو خاص معاملہ ایڈمنسٹریشن کا نہیں ہے اور وزیر داخلہ صاحب کے ایکشن لینے کا بھی نہیں ہے - یہاں سعولنکی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ چلے گئے - شنکر بھائی پٹیل بھی بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی چلے گئے - دوسرے ہمارے گجرات کے لیڈرس بیٹھے ہوئے ہیں - میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپکو خود گجرات کی سرزمین پر جو کمیونل ٹینشن پچھلے دس سال کے اندر بڑھا ہے اور جو جاتی وادی نفرت بڑھی ہے اسکو چیک کرنے کیلئے کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونڈنا چاہیئے - میرا یہ ماننا ہے کہ پالیٹیکل لوگ بہت جگہوں پر ذمہ دار ہیں - لیکن ایک وہ واقعہ ... "وقت کی گھنٹی" ... اسکو عام طور پر نظر انداز کرتے ہیں - وہ ہے بیوروکریسی - آج بیوروکریسی ملک کے اندر نسطح سے گر رہی ہے - ابھی وزیر داخلہ صاحب پورے واقعے میں - میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پولیٹیکل آدمی کو بھی گالی پڑ رہی ہے - لیکن ایک پورا ایڈمنسٹریشن جسکو کرودھ میں صاحب نے اشارۃً کہا - میں یہ کہتا ہوں کہ آج گجرات کا جو پورا ایڈمنسٹریشن ہے جسکے اندر بیوروکریسی بھی شامل ہے اور جسکے اندر پولیس بھی شامل ہے - اسکا رویہ کیا ہے - ذرا سا پالیٹیکل اشارہ ہوتا ہے تو وہ آگے بڑھکر اس سے کہیں زیادہ وہ کام نیچ کرنے کا کام کرتے ہیں اس سے زیادہ ظلم کرنے کا کام کرتے ہیں - تو خاں صاحب سوال یہ نہیں کہ منسٹر کو ہٹا دیا جائے گا تو مسئلہ حل ہو جائیگا - گجرات کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیجئے پچھلے دس سال کے اندر گجرات میں کیا ہوا ہے - ۱۹۸۳ میں کمیونل رائٹ ہوا تھا - اسکے واقعات مجھے آج تک یاد ہیں - جو کمیونل رائٹ ہوتے رہے ہیں مجھے انکا انوبھو ہوا ہے - چونکہ اپنے اسے جبرنلسٹ ایسی جگہوں پر گیا ہوں اور وہاں جا کر میں نے دیکھا ہے - دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھکو کوئی اعتراض نہیں ہے اسکو کہنے میں - میں ایک مہاراشٹر کے فرقے سے آیا ہوں اور گجرات کے بہت

ہم لوگوں کی کانسٹی ٹیونسی ہے۔ ہم لوگ پانچ سال۔ چھ سال کے بعد عوام کے سامنے جواب دہ ہیں۔ لیکن وہ سرکاری ملازم جو ایک بار آئی۔ اے۔ ایس۔ کا امتحان پاس کر کے آگیا۔ اسکی جواب دہی کتنی ہے علاوہ اسکے کہ اسکا ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ اگر پولیس اور ایڈمنسٹریشن میں خرابی ہے تو آپکو اس جاپ کو بھی دیکھنا ہوگا۔ میں یہ مانتا ہوں گالی دینے کا بڑا رواج ہے ہمارے یہاں پالیٹیکل لوگوں کو۔ یہاں ایک منسٹر انوالو ہے۔ باقاعدہ انکوائری ہونی چاہیئے تھی لیکن ایڈمنسٹریشن کو ہدایت ایگزی کیوٹیو کو یہ پابندی ہے کہ اگر کوئی پالیٹیکل آدمی غلط حکم دیتا ہے تو اس کو ماننے سے انکار کر دے۔ کیوں پولیس نے اسکے کہنے سے ایسا کیا کیوں پولیس نے ایسا نہیں

نے چیف منسٹر کی چار تاریخ کو میٹنگ کی تھی۔ اسمیں اپنی ایک رپورٹ پیش کی تھی اسمیں تین اسپیکٹ سے رپورٹ آئی کہ اگر "ٹاڈا" جاری رہتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں اور ان تینوں اسپیکٹ کے اندر جب چیف منسٹر کے بیانات آئے تو انھوں نے کہا کہ "ٹاڈا" کے بالکل خلاف ہیں۔ اندر جا کر دیکھا کہ بیوروکریٹ نے اپنی رپورٹ تیار کر کے سینٹرل گورنمنٹ کو بھیجوی اور سینٹرل گورنمنٹ نے اپنی رپورٹ بنا کر بھیجوی۔ وہ بھی بیوروکریٹ کے ہاتھوں۔ اب آپ لوگ تک اس ملک کو بیوروکریٹس کے ہاتھوں اس طرح سے چلاتے رہینگے۔ جب سیاسی لوگ اپنے طور پر ناکام ہوتے ہیں تو نیچے کے لوگ ان سے زیادہ نقصان پہونچانے کی کوشش کرینگے کوئی چیک نہیں ہے آج بیوروکریسی کے اوپر۔ کون سا چیک ہے اس پارلیمنٹ کے اندر۔ اس پارلیمنٹ کے اندر اگر میں کوئی نام لیتا ہوں تو سر۔ آپکی چیئر سے آبجیکشن ہوتا ہے۔ کہ جو آدمی اپنے آپ کو ڈفینڈ نہیں کر سکتا۔ اسکا نام نہیں لیا جا سکتا۔

کیا کہ منسٹر وہاں کھڑا ہوا تھا تو کوئی کارروائی
نہیں کی - اسلئے پولیس کے لوگ بھی ذمہ دار
ہیں - اسلئے انکوائری جب ہو تو ان سارے
آسپیکٹس کو دیکھنا چاہیئے - اور بنیادی
جو مسئلہ ہے گجرات میں - اس پر ہم سبھی
کو دھیان دینا چاہیئے - بہت بہت شکریہ -
"ختم شد"]

SHRI GOPALSINH G. SOLANKI (Gujarat): Mr. Vice-Chairman, Sir, arguments have been advanced and submissions have been made by hon. friends on this subject. But what I would like to say is that the root cause of this particular quarrel could have been submitted well, in the manner in which it is required. The cause of the quarrel was that there were some group of anti-social elements who had started ruining the whole socley. They were going to the hotels, but not paying the bills. Not only that, they were threatening the hotel owners that if they asked them to pay the bills, then they would file a complaint against them under the Prevention of Atrocities Against the Schedule Castes and Scheduled Tribes Act. This was the root cause. After this quarrel arose, unfortunately it was found that the involvement of the Dalits was there and the sufferers were the Dalits. I also want to say that it is a sad incidetn which has taken place. So far as the presence of a Minister, Shri Nitin Patel, was concerned, I would like to say that he was in his native kadi town. It was not that as if he was present at the time of the incident or that he was involved either directly or indirectly In fact, he had rushed to the spot immediately to prevent the incident from further escalating. Not only that, the Government has paid compensation to the victims. An investigation is being conducted by an officers not below the rank of Dy. S. P. The BJP Government has not done anything contrary to the investigation Whatever is going to come out of the inquiry, they will take action accordingly and book the culprits and put them behind bars. Thank you.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : माननीय सभापति जी, जो दुर्घटना गुजरात के मेहसाना जिले में घटित हुई, वह बहुत ही शर्मनाक और घृणित है और उसकी जितनी भी निंदा की जाए, वह बहुत कम है लेकिन मैं केवल दो तीन सुझाव देना चाहता हूं । मैं गुरूदास दासगुप्त जी की बात से पूर्ण तरीके से सहमत हूं कि सारे मामले की जो न्यायिक जांच है, वह सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के द्वारा कराई जाए कमीशन्स आफ इनक्वायरीज एक्ट 1952 के तहत और वह इनक्वायरी तो होती ही रहेगी लेकिन जो लोग उस घटनास्थल पर मौजूद थे और जिन्होंने इस तरीके की शर्मनाक घटना में भाग लिया, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए । जैसा कहा जा रहा है कि उसमें एक मंत्री भी थे तो कम से कम वहां के मुख्य मंत्री को इस मंत्री को अपने मंत्रिमंडल से बरखास्त कर देना चाहिए या उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लेना चाहिए ।

श्री चतुरानन मिश्र : त्याग-पत्र देगा तब स्वीकार करना चाहिए ना ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : लेकिन अगर मुख्य मंत्री ऐसा नहीं करते तो वहां के राज्यपाल को मंत्री महोदय को बरखास्त कर देना चाहिए । दूसरे, जो घटना हुई, उसकी थाने में रिपोर्ट भी

†[ ]Transilteration in Arabic Script

[सत्य प्रकाश मालवीय]

हुई है। वहां की पुलिस मामले की जांच नहीं कर सकती है इसलिए यह सारा मामला कोई उच्च स्तरीय टीम को दिया जाए। जयपाल रेड्डी जी ने सुझाव दिया था कि इसको सी०बी०आई० को सौंपा जाए लेकिन सी०बी०आई० को तभी सौंपा जा सकता है जबकि राज्य सरकार केन्द्र सरकार से अनुरोध करे। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसकी जांच एक उच्च स्तरीय टीम के द्वारा कराई जाए और जो लोग इसमें कम से कम वहां पर मौजूद थे, इस दुर्घटना के समय, इस घटना के दोषी है, अपराधी हैं, उनको गिरफ्तार करके जेल मे डाल दिया जाए क्योंकि जो लोग सत्ता में हैं, वे जब अत्याचार करते हैं, विशेष रूप से दलितों के ऊपर या किसी वर्ग के ऊपर करें तो बहुत ही निंदनीय है। इसलिए जो दो तीन सुझाव दिए हैं, एक तो कमीशन्स आफ इनक्वायरीज एक्ट के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के सिटिंग जज से जांच कराई जाए। इसलिए सारी घटना की जांच किसी उच्च स्तरीय टीम से कराई जाए और अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। तीसरे मंत्री, महोदय का त्याग पत्र वहां के मुख्य मंत्री स्वीकार करें और यदि ऐसा नहीं है तो राज्यपाल उस मंत्री को बरखास्त करें।

श्री गुंडप्पा कोरवार (कर्नाटक): उपसभाध्यक्ष जी, यह जो दलितों के ऊपर जुल्म होते चले आ है है, यह कोई नयी बात नहीं है। यह जो सोसायटी है, समाज है, उसकी यह फितरत है कि सदियों से दलितों को वह सताते आए हैं, उन पर जुल्म करते आए हैं। यह जो गुजरात की घटना है, यह हमारे लिए नयी बात नहीं है। हमारे बी०जे०पी० के साथी यह कहते हैं कि उसकी मूल वजह यह है कि वह जो दुकान से सामान लेते थे, उसका पैसा नहीं देते थे, होटल में जो चाय पीते थे, उसके पैसे नहीं देते थे, यह कोई बात नहीं है। अब तक इस मुल्क के दलित अपना सर उठाकर हिम्मत नहीं कर सके कि मैं किसी के ऊपर जुल्म करूं, किसी को गाली दूं या किसी की प्रापर्टी हड़पूं, हासिल करूं। ऐसा नहीं हुआ है। इस मुल्क के दलित ऐसे हैं जो यह सोचते हैं कि "या रब, किसी से छीनकर हमको खुशी न दे और जो औरों पर भार हो वो जिन्दगी न दे।" वह ऐसे लोग हैं जो सदियों से इतने जुल्म और सितम बर्दाश्त करते आए। अगर हिस्ट्री को आप देखें तो दुनिया की किसी हिस्ट्री में ऐसी चीज नहीं मिलती जो जुल्म और सितम इस कौम पर हुए, इन जातियों पर हुए। ऐसे जुल्म और किसी मुल्क मे नहीं हुए। इस प्रकार हम जी रहे हैं, इस मुल्क में। यह सब हम बर्दाश्त कर रहे हैं जिसे हर कोम बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज हम जरा सिर उठाकर बात करें तो दूसरों को ठेस लगती है, गुस्सा आता है कि दलित का सिर उठा, उसे मस्ती आयी है। इस प्रकार की फितरत है इसान की क्योंकि सदियों से हम दब रहे, जुल्म के शिकार रहे, शोषण के शिकार रहे और हमेशा दबाव में हम जीते रहे। लेकिन अब जो नौजवान बच्चे हैं, पढ़े-लिखे लोग हैं, ज्ञान हासिल किए हुए है, वह दुनिया को जानते है, वह सब जब अपने हक के लिए स्वाभिमान से आगे आते है, अपने हक को हासिल करने के लिए आगे आते हैं तो औरों के लिए यह बड़े गुस्से की बात हो जाती है, नफरत की बात हो जाती है। इसलिए जो गुजरात में घटना घटी है, वह न सिर्फ गुजरात में बल्कि मुल्क के हर कोने में सदियों से घटती आ रही है। इसलिए हम कहते हैं कि बर्दाश्त करने की जो शक्ति है, वह इस मुल्क के दलितों में है और अब तक वह बर्दाश्त करते आए हैं। कहीं भी अगर हद से बढ़कर जुल्म होता है या हम स्वाभिमान से अपना हक हासिल करने को कदम बढ़ाते हैं और अगर उसमें दिक्कत पैदा की जाती है या हम पर जुल्म होता है तो मजबूरन अपना हक हासिल करने के लिए हमको लड़ना पड़ता है। इसलिए अब जमाना गया उस बात का कि गांव का साहूकार गांव का कुलकर्णी हमको दबाकर रखता था। अब हालत ऐसी नहीं है। अब हम भी जीना चाहते हैं, हिम्मत

जीना चाहते हैं, आजादी से जीना चाहते है, स्वाभिमान से जीना चाहते हैं, किसी की मेहरबानी पर नहीं रहना चाहते। इसलिए यह मौका हमको हासिल हुआ है। चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, किसी भी पार्टी के मेंबर हों, यह पार्टी के हिसाब से सोचने की बात नहीं है। यह मुल्क का सवाल है, समाज का सवाल है, समानता का सवाल है, स्वाभिमान का सवाल है, सदियों से दबे हुए लोगों की जिन्दगी का सवाल है। उनके लिए हमदर्दी होनी चाहिए। इंसान बने तो क्या हुआ अगर इंसान के दिल में हमदर्दी नहीं है तो इंसान को लेकर क्या करना, इंसान बनकर क्या करना ? दबे हुए जो लोग हैं, उनके लिए हमदर्दी नहीं है, दर्द नहीं है तो इंसान बनना बेकार है। यह एक ऐसी घटना हुई है, सरकार में मंत्री जो है वह उनकी सफाई दे रहे हैं, उनका डिफेंस करना उनका काम है, लेकिन लोग जानते हैं कि वहां क्या हुआ। जो आदमी मंत्री है, उस मंत्री के सामने यह हादसा होता है और मंत्री के सामने सब लोग गांव छोड़कर जाता हैं। हरिजन और दलित लोग बोरे-बिस्तर सर पर रखकर जाते हैं और कहते हैं कि हम यहां परेशान हैं, हमारा यहां जीना मुश्किल है। यहां पर हमारी जान खतरे में है। यह समझकर वे गांव से बाहर जा रहे थे और मंत्री उनको, बैठकर देख रहा था। उसकी यह हिम्मत नहीं हुई यह कहने की, आपको यहीं जीना है, आपकी हिफाजत हम करेंगे हम आपको जाने नहीं देंगे। यह हमारा अपमान है, हमारी सरकार का अपमान है। हम आपको जाने नहीं देंगे। वहां बी.जे.पी. की सरकार है इसलिए यह इल्जाम नहीं है। लेकिन सवाल यह हैं कि कोई आदमी, हमारा पड़ोसी या हमारे बाजू में रहने वाला हो और उस पर जुल्म होता हो और वह अपना सामान उठाकर भाग जाना चाहता है कि मेरा यहां जीना मुश्किल है तो क्या उसकी हिफाजत वहां के लोग, वहां की सरकार, वहां की पुलिस नहीं करेगी ? वहां के लोगों को उनको कहना चाहिए कि आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा। लेकिन इस तरह की जो घटनायें हैं वे घटती आ रही हैं और इसकी रोकथाम के लिए सख्ती से पेश आना जरूरी है। लेकिन क्या होता है कि सरकार और पुलिस, जिसके पास कानून की ताकत है, ये आपस में मिल जाते है। जब हम लोग पुलिस के पास कम्पलेंट करने जाते हैं कि हमारे ऊपर जुल्म हुआ है तो उसके पहले जुल्म करने वालों की अप्ती-केशन रजिस्टर हो जाती है। यह हमारा तजुर्बा है। इस मुल्क में हमारे सामने इस तरह की घटनायें हुई हैं और हो रही है। हमारे सामने जैसे जानवरों को काटा जाता है उसी तरह से हरिजनों को काटकर फेंका जाता है। यह हमारे सामने हुआ है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। इसलिए यह समाज, जो इस तरह का समाज है इसको सुधारने की जरूरत है। संतों, साधुओं और समाज सुधारकों और बहुत से लोगों ने इस चीज को दूर करने के लिए अपने विचार रखे हैं, इस समाज को सुन्दर बनाने के लिए विचार रखे हैं। वहां पर जो घटना हुई है उसको छिपाने की कोई बात नहीं है। अगर वहां पर किसी हरिजन ने भी गुनाह किया है तो उसको भी सजा मिलनी जरूरी है, यह कहने में मैं पीछे नहीं हटता। लेकिन एक किस्सा बनाकर, कहानी बनाकर इस तरह से.....

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (उत्तर प्रदेश): मैं आपकी बात नहीं काट रहा हूं। माननीय, चेयरमैन साहब के साथ सुबह बात हुई थी, मैडम भी उस समय उपस्थित थी। चेयरमैन साहब ने कहा था क्योंकि आज कोई विशेष ऐसा काम नहीं है, पूरा काम हो जाएगा, इसलिए लंच आवर होगा। तो मेरा निवेदन है कि लंच आवर की छुट्टी नहीं करनी चाहिए। बाद में आप इसको चलाए रखिए लेकिन लंच आवर तो होना चाहिए।

SHRI AJIT P. K. JOGI: Sir, the hon. Home Minister may kindly react. We are anxiously waiting for

the Home Minister to react to it. (*Interruptions*) . . .

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : मैं विरोध नहीं कर रहा हूं । मैं यह कह रहा हू कि चेयरमैन साहब के कमरे में–पचौरी जी भी थे, यह तय हुआ था कि आज लंच आवर होगा । क्योंकि स्पीकर साहब ने बहुत से लोगों को लंच पर बुलाया है । उस समय मैडम ने भी कहा था कि लंच आवर जरूर होगा और चेयरमैन साहब ने भी स्वीकार किया था । मैं मामले को बंद करने की बात नहीं कर रहा हूं । लंच आवर होने दीजिए, जिससे हम स्पीकर महोदय के यहां भी जा सकें । बहुत से मेंबर वहां जाने वाले है । मेरा निवेदन है कि यह मामला चलाए रखें लंच आवर होने दीजिए ।

श्री दिग्विजय सिंह : पहले यह बता दीजिए कि लंच आवर होगा या नहीं ?

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) : सुबह जब चर्चा हुई थी तो उस समय यह विषय नहीं आया था ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : विषय आया था और चेयरमैन साहब ने कहा था कि . . . (**व्यवधान**) . . . ऐसा नहीं है ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): I have listened to you and understood as to what you want. (*Interruption*) The House is supreme. If you want that we should sit through and complete this debate, we can do that. (*Interuuptions*)

श्री राजूभाई ए. परमार: होम मिनिस्टर साहब यहां बैठे हुए हैं उनको . . . (**व्यवधान**)

श्री गुंडपा कोरबार : मैं चाहता हूं जो इसमें शामिल हैं, उनके खिलाफ एक्शन जरूर होना चाहिये । मैं डिमांड करता हूं कि ज्यूडिशियल इन्क्वायरी होनी चाहिये । जो लोग इस घटना के शिकार हो गये हैं, उनका जितना नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई होनी चाहिये । जब वे वापिस आ जाएं तो उनको पूरा प्रोटेक्शन मिलना चाहिये । यह कहते हुए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं ।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) : श्री सी. एस. शुक्ला । बहुत सी बातें आ चुकी हैं इसलिए मुख्तसर बोलिए ।

श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल (गुजरात)

Sir, I will not repeat anything. आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैंने आदरणीय जोगी जी की पूरी रिपोर्ट देखी है । एक बात उसमें नहीं है, यह जो पूरी बातें यहां पर कही गई है यह कहने का अवसर ही नहीं आता यदि उन्होंने कनसर्ड मिनिस्टर को भी मिल लिया होता । आखिर उनका क्या कहना है । In the court the accused is given a chance to explain his position . . . (*Interruptions*) . . .

SHRI AJIT P. K. JOGI: Will the hon. Chief Minister be kind enough to . . . (*Interruptions*) . . .

श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल: मैं चीफ मिनिस्टर की बात नहीं कर रहा हूं जोगी जी । मैं नितिन पटेल की बात कर रहा हूं । आपने नितिन पटेल को मिलने की कोशिश नहीं की । इसलिए कोशिश नहीं की कि आप कुछ लूपहोल्ज रखना चाहते थे । कई बातें इधर कही गई । स्वर्णों के मकान भी जल गये हैं, माइनारिटीज के मकान भी जल गये हैं, यह सारी बातें जो हुई हैं, यह इसलिए हुई हैं कि मुफ्त में माल लेना, दादागिरी करना, गुंडागर्दी करना, लोगों को तंग करना, उसकी वजह से हादसा हुआ है ।

I do not defend it. लेकिन जो हुआ है, वह ठीक नहीं हुआ है । लेकिन आपको यह भी देख लेना चाहिये कि आखिर क्यों हुआ ? इधर आदरणीय सदस्यों ने बताया कि आखिर हम पक्षधर किस के हैं ? मैं आपको बताना चाहता हूं जोगी जी जिसके लिए आप सब लोग

[श्री चिमन भाई हरि भाई शुक्ल]

जल रहे हैं 13 में से 10 सीटें शेड्यूल्ड कास्ट्स की बी.जे.पी. को मिली हैं । जो छिन गई हैं वह एक हजार वोट से नीचे गई है । आज पूरा पिछड़ा वर्ग बी.जे.पी. के साथ है । इसलिए आप यह सब कर रहे हैं । (व्यवधान)

श्री राजूभाई ए. परमार : आप जाकर देख लो किसके साथ हैं (व्यवधान)

श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल : मैंने देखा है, मैं वहीं से आता हूं राजूभाई, मैं सब जानता हूं । मेरे लिए कोई बात नई नहीं है । न आप नये हैं और न आपकी सोच नई है । आदरणीय उपसभाध्यक्ष जी, जो गोयेबल्ज का भाषण होता था मैं छोटा बच्चा था, लेकिन आज मुझे लगता है कि गोयेबल्ज के भाषण किस तरह के होते होंगे । एक बात बार-बार रिपीट करने से यह सच नहीं हो जाता है । गुजरात सरकार को कटघरे में खड़े करने की बात कर रहे है, सरकार को डिसमिस करो, क्यों डिसमिस करें ? एक हादसा हुआ । हादसा कैसे हुआ ? क्या मिनिस्टर था वहां ? किसी ने पूछा नहीं कि वहां मिनिस्टर था या नहीं । मिनिस्टर वहां जगह पर था ही नहीं, उसने इंस्टीगेट किया ही नहीं, यह सब लोग जानते है । फिर यह बातें क्यों हो रही हैं ? इसलिए मैं यह कहता हूं कि इस बात को पोलिटिकल कलर मत दो, आप जो कोशिश कर रहे हैं, वह बेकार कोशिश है । इससे कुछ होने वाला नहीं है । वहां का पिछड़ा वर्ग, हरिजन तबका आज भी बी.जे.पी के साथ है और कल भी रहेगा थैंक यू ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Shri Muthu Mani. Please be brief

SHRI S. MUTHU MANI: Thank you, Sir I will take only one minute.

Sir, I join my exteemed colleagues in condemning the atrocities committed on the helpless Scheduled Caste people. It is a matter of regret that thousands of people led by a Minister had unleashed terror among the innocent people. Sir, it is all the more wounding to know that so far, no one has been brought to book in spite of it being a heinous crime committed by influential people. Even the Minister responsible for this shameful incident has not been sacked so far Sir, through you, I want to submit that this kind of silence will only encourage the anti-social elements, leading to confusion and chaos in the society. Sir, it is the duty of the Government to provide solace to the affected people. Therefore, I demand a judicial probe by a sitting Judge of the High Court into the matter. I request that an ex gratia payment of at least Rs. 25,000/- be given to each affected family. Sir, adequate compensation in proportion to the loss of property and injury should be provided to all the victims. All the administrative and the police officials who were mute witnesess to the incident should be transferred forthwith and disciplinary proceedings should be initiated against them. All those who are responsible for this inhuman incident should be put behind bars, irrespective of their social status. Then alone the SC/ST people will regain confidence in the administration and the society.

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) : श्री चतुरानन मिश्र । एक मिनट में बोल दीजिए ।

श्री चतुरानन मिश्र यह तो बहुत ही दर्दनाक घटना है आप जानते हैं । इसकी जितना निंदा की जाए वह भी कम है । लेकिन एक बात हुई है कि वहां बी०जे० पी० की सरकार और हमारे लीडर आफ दी आपोजीशन बी.जे.पी. के हैं । उन्होंने एक आफर किया है कि कुछ टाइम

दीजिए । तो हम होम मिनिस्टर साहब से जो हमारे लीडर आफ द हाउस भी है, अनुरोध करेंगे कि इस डिबेट को परसों हम लोग कनक्लूड करें कल आप...

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : यह डिबेट है ही नहीं । यह तो जानकारी हासिल करके जब हाउस के सामने आते हैं अगर आप सब लोग यह कहते हैं कि इसे डिबेट में कन्वर्ट किया जाए तो मेरे पास जो पूरी जानकारी आएगी उसके बाद फिर डिबेट नही होगी ।

श्री चतुरानन मिश्र: होगी । हमारी बात सुन लीजिए । हमने कहा कि यह जो अभी बहस है इसको हम जारी रखना चाहते हैं आप कल चीफ मिनिस्टर....

श्री एस० बी० चव्हाण : नहीं, नहीं । हमारे पास पूरी तफसील आने के बाद फिर कीजिए ।

श्री चतुरानन मिश्र : हमारी बात तो आप कंपलीट सुन लीजिए तब पूरा आ जाए तो ठीक है । लॉ की जैसी पोजीशन है आप भी जानते हैं लिमिटेशन है, आप भी क्या कर सकते हैं ...

श्री एस० बी० चव्हाण : आपको भी मालूम है ।

श्री चतुरानन मिश्र : और हाउस हैल्पलेस हो जाता है । अगर एक आफर आया है तो हम चाहते थे आज रात या कल चीफ मिनिस्टर से बात कर लीजिए । वे आए, लीडर आफ द आपोजीशन रहें, आपके सामने बातचीत हो जाए । अगर यह बात निकल आए कि हां वे उस मिनिस्टर को हटाना चाहते हैं या जुडीशियल इंक्वायरी पर वे राजी हैं या सी.बी आई. को देना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं तो यह सब रिपोर्ट आप कल नहीं परसों हमारे सामने रख दीजिए । फिर हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे बातचीत के आधार पर जो निकलेगा । नही तो होता क्या है कि जुल्म से जुल्म होना है हम लोग ऐसे ही बहस करके बाद में लंच में चले जाते हैं । हमारा ख्याल है कि इसको लंच में मत भेजिए । कुछ कीजिए जिससे देश को विश्वास हम लोगों पर हो कि यह पार्लियामेंट कुछ करने में सक्षम है । यही हमारा एक मिनट में आपसे अनुरोध है ।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) : श्री दिग्विजय जी आप भी एक मिनट ही बोलिए ।

श्री दिग्विजय सिंह : सारी बातें हो चुकी हैं मैं इसमें कुछ बहुत ज्यादा नहीं जोड़ना चाहता हू । मुझे खुशी इस बात की है आज कि इस बहस में बी.जे.पी. के लोगों और उनके नेताओं ने जो रूख अपनाया है वह सराहनीय रूख है । चतुरानन जी ने बिल्कुल सही बात कही है कि अगर उन्होंने समय मांगा है तो उस समय का सही सदुपयोग किया जाए और गृह मंत्रालय उस पर एक्शन में आए । चीफ मिनिस्टर से जांच करवाए पूछे कि हकीकत क्या है । अगर सचमुच यह सही है कि वहां के मंत्री का, जिनका नाम बार-बार लिया गया है, इस घटना से संबंध जुड़ा हुआ है तो जो स्पिरट आज नेता विपक्ष दल ने दिखलायी है मुझे तो लगता है कि बी०जे०पी० के मुख्य मंत्री शायद खुद ही उनको हटा देंगे । ऐसा उनके बयान से मुझे लगा । अगर ऐसा नही करते हैं तो संविधान में देश मे, सारी पार्टियों मे एक ही समझौता है कि अंदर से जो कुछ करें लेकिन ऊपर से सारी पार्टियां एक राय पर है कि गांधी के दिए गए आश्वासन के मुताबिक इस मुल्क के दलितों की जिंदगी को सुधारना है उसको बेहतर बनाना है तो आज मैं समझता हूं कि उस मौके का फायदा गृह मंत्री जी को उठाना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा जो संविधान के अंतर्गत उनके पास है उसके हिसाब से इसमें कदम उठाएं । यही म एक मिनट में शब्द कहकर समाप्त करता हूं ।

उपसभाध्यक्ष श्री मोहम्मद सलीम : मौलाना अबैदुल्ला जी, आधा मिनट बोल दीजिए ।

मौलाना अबैदुल्ला खान आज़मी (उत्तर प्रदेश : मैं आधे मिनट से भी आधे में कहने की कोशिश करूंगा । मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि यह जो दर्दनाक हादसा हुआ है गुजरात में दलितों के साथ यह लायके मजम्मत है । पूरे हाउस के साथ साथ मैं भी इसकी मजम्मत करता हूं । अभी हमारे बी.जे.पी. के भाइयों ने एक बात कही थी कि इसको पोलिटिकल मत बनाइए । यकीनन इसको पोलिटिकल नहीं बनाना चाहिए । उन्होंने दावा किया था कि बी.जे.पी. के लोगों के साथ वहां के दलित हैं । यह दावा भी हम मान लेते हैं । अफसोस इस बात का है कि हर सूबे से लोग दलितों के बारे में यह कहते हैं, जिसकी भी हुकूमत हो, कि दलित हमारे साथ हैं । मगर अफसोस यह है कि दलितों के साथ कोई दिखलाई नहीं देता है । यह दावा तो बहुत ऊंचा है कि दलित आपके साथ हैं । जो दलित आपके साथ था वह दलित वहां फूंका गया, मारा गया इससे ज्यादा आपके लिए शर्म की और क्या बात हो सकती है । उस दलित को अन्याय से मुक्ति दिलाने के लिए उसके साथ इन्साफ करने के लिए जो मिनिस्टर इस वक्त कंट्रोवर्सी का शिकार बना हुआ है ईमानदारी के साथ उस मिनिस्टर की जांच करवाई जाए और मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए ताकि आपका यह दावा सही साबित हो कि दलित आपके साथ हैं और दलितों के साथ आपने जो अन्याय किया है उसके खिलाफ आपने न्याय किया है । दलित सबके साथ है मगर दलितों के साथ कोई नहीं है । यह इस मुल्क का दुर्भाग्य है, इस मुल्क के लोगों का दुर्भाग्य है, हम सबका दुर्भाग्य है । दलितों के साथ होने वाले इस जुल्म के खिलाफ मैं जबर्दस्त मजम्मत करता हूं और होम मिनिस्टर साहब से मांग करता हूं कि व आश्वासन दें कि आइंदा ऐसी हरकत नहीं होगी ।

†مولانا عبیداللہ خاں اعظمی (اتر پردیش): میں آدھے منٹ سے بھی آدھے میں کہنے کی کوشش کرونگا - میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو دردناک حادثہ ہوا ہے گجرات میں دلتوں کے ساتھ یہ لائق مذمت ہے - پورے ہاؤس کے ساتھ میں بھی اسکی مذمت کرتا ہوں - ابھی ہمارے بی - جے - پی کے بھائیوں نے ایک بات کہی تھی کہ اسکو پولیٹیکل مت بنایئے - یقیناً اسکو پولیٹیکل نہیں بنانا چاہیئے - انھوں نے دعویٰ کیا تھا کہ بی - جے - پی کے لوگوں کے ساتھ وہاں کے دلت ہیں یہ دعویٰ بھی ہم مان لیتے ہیں - افسوس اس بات کا ہے کہ ہر صوبے سے لوگ دلتوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں جسکی بھی حکومت ہو کہ دلت ہمارے ساتھ ہیں مگر افسوس یہ ہے کہ دلتوں کے ساتھ کوئی دکھائی نہیں دیتا ہے - یہ دعویٰ تو بہت اونچا ہے کہ دلت آپکے ساتھ ہیں - جو دلت آپکے ساتھ تھا وہ دلت وہاں پھونکا گیا - مارا گیا - اس سے زیادہ آپکے لئے شرم کی کیا بات ہو سکتی ہے - اس دلت کو انیائے سے مکتی دلانے

†[ ]Transilteration in Arabic Script

کیلئے اسکے ساتھ انصاف کرنے کیلئے جو معزز
اسوقت کنفرنس رسمی کا شکار بنا ہوا ہے
ایمانداری کے ساتھ اس منسٹر کی جانچ کروائی
جائے اور مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا
جائے۔ تاکہ آپکا یہ دعویٰ صحیح ثابت
ہو کہ دلت آپکے ساتھ ہیں۔ مگر دلتوں
کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ یہ اس ملک کا
"دوبھاگیہ" ہے اس ملک کے لوگوں کا "دوبھاگیہ"
ہے۔ ہم سب کا "دوبھاگیہ" ہے۔ دلتوں
کے ساتھ ہونے والے اس ظلم کے خلاف
میں زبردست مذمت کرتا ہوں اور
پھر منسٹر صاحب سے مانگ کرتا ہوں
کہ وہ آشواسن دیں کہ آئندہ ایسی
حرکت نہیں ہوگی۔ "ختم شد"]

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Mr. Home Minister, do you want to say something?

SHRI S. B. CHAVAN: I will react to it.

Mr. Vice-Chairman, Sir, some hon. Members, specially Mr. Jogi, have raised this issue and all the Members from all sides of the House have supported the demand. They also know the limitations of the Constitution. The hon. Members, Shri Chaturanan Mishra, said, "We are aware of the fact that under the Constitution the Government of India can go to a particular length and beyond that it is impossible for the Government of India to take any action because it is a question of Centre-State relations." When it comes to Gujarat the Members say, "You do this and you do that." The hon. Member has gone to the extent of Member has gone to the extent of saying that if the Chief Minister does not agree, we should ask the Governor to do it. This is something which, in fact, I cannot possibly think of.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: I have not said that. What I said was that the Chief Minister should ask the concerned Minister to resign. If the Minister does not resign, then the Governor should sack him. I have not requested you to ask the Governor. (*Interruptions*). I have not requested you to ask the Governor.

SHRI CHATURANAN MISHRA: The Governor has no power to dismiss any Minister.

SHRI S. B. CHAVAN: It is a question of the system in its entirety. We have to consider that. Whether the incident took place in one area or the other, it is totally irrelevant. This, in fact, is a very shameful thing. We have been repeatedly saying that all the State Governments should take immediate action to retore confidence among the weaker sections of the society and among the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. In spite of that, there are incidents which are happening. It, in fact, does not give credit to any society, for that matter any Government. But, I am prepared to go to the extent that Mr. Chaturanan Mishra has suggested. I will write, I will speak to the Chief Minister of Gujarat to submit a report. I consider it very serious because of the fact that it is alleged that one of the Ministers of the Government was also involved in it. How far it is true, it is not for me to say.

After I get the report, if I feel that there is something about which I should discuss with the leaders of the Opposition and thereafter try to find a solution, try to see how best we can find a way out, certainly we will try our level best. Thereafter, I will come to the House and report to you and tell you the ultimate outcome of the discussion that we held today.

SHRI CHATURANAN MISHRA: Before the Session ends;

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): I adjourn the House for lunch for one hour.

The House then adjourned for lunch at forty-eight minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at forty-nine minutes past two of the clock, **The Vice-Chairman (Shri Suresh Pachouri)** in the Chair.

MOTION REGARDING THE SEVENTH REPORT OF THE COMMITTEE ON RULES—CONTD.

SHRI RAMESHWAR THAKUR: With reference to the motions regarding the seventh report of the Committee on Rules, in deference to the wishes of the Members, I move that:

"(iv) The proposed New Rule 40 A be *deleted*."

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): I shall now put the amended motion to vote.

I. "That the Seventh Report of the Committee on Rules presented to the Rajya Sabha on the 14th February, 1995 be taken into consideration."

II. "That this House agrees with the recommendations contained in the Seventh Report of the Committee on Rules, presented to the Rajya Sabha on 14th February, 1995 with the following amendments, namely:

(i) In the proposed amendment to sub-rule (2) (vii) of Rule 47 *for* figures "50" *substitute* figures "100".

(ii) In the proposed new Rule 51 (A) *for* figures "150" *substitute* figures "175".

(iii) Committee's recommendation regarding the acceptance of notices on FAX may be *deleted*.

(iv) *The proposed* New Rule 40 A be *deleted*."

The motions was adopted.

THE NATIONAL ENVIRONMENT TRIBUNAL BILL, 1995.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): Mr. Vice-Chairman Sir, I beg to move:

"That the Bill to provide for strict liability for damages arising out of any accident occurring while handling any hazardous substance and for the establishment of a National Environment Tribunal for effective and expeditious disposal of cases arising from such accident, with a view to giving relief and compensation or damages to persons, property and the environment and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

In doing so I submit that this Bill seeks to fulfil a long-felt demand for some mechanism for effective and expeditious relief and compensation for damages to persons, propert and